

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 194 बेमेतरा, रविवार 08 मार्च 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्गा/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

मिडिल ईस्ट संकट का असर भारत की रसोई तक



नई दिल्ली। देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय हालात और कच्चे ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब घरेलू बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। खासतौर पर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के कारण ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है, जिसका असर एलपीजी की कीमतों पर भी पड़ सकता है।

अब जन्म के साथ बनेगा आधार

नई दिल्ली। भारत में आधार कार्ड आज सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक बन चुका है। बैंक खाता खोलवाने से लेकर मोबाइल सिम खरीदने, स्कूल में दाखिला कराने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आधार की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण सरकार लगातार पहचान से जुड़े दस्तावेजों को आपस में जोड़कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है।

केंद्र ने ग्रीन अमोनिया और मेथनॉल के लिए नए मानक तय किए

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को गति देने के लिए शनिवार को ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के लिए नए मानक अधिसूचित किए। इन मानकों का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन से बनने वाले ईंधन के व्यापार और उपयोग को बढ़ावा देना है। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, ये मानक 27 फरवरी 2026 को अधिसूचित किए गए हैं। इनमें यह तय किया गया है कि किन शर्तों और उत्सर्जन सीमा के तहत अमोनिया और मेथनॉल को ग्रीन श्रेणी में रखा जाएगा।

सरकार ने निर्यातकों को राहत देने के लिए उठाया कदम

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में आए व्यावधान के बीच सरकार ने निर्यातकों को राहत देने का मन बनाया है। इस बारे में सरकार की ओर से शनिवार को कुछ बड़े एलान किए गए। पिछले महीने ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के साझा हमले के बाद व्यापारिक जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में निर्यातकों को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 'लखपति दीदी संवाद', लखपति दीदियों ने सुनाई सफलता की कहानी

महिला सशक्तिकरण के नवयुग की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़: सीएम

रायपुर। छत्तीसगढ़ की महिलाएं आत्मनिर्भरता, मेहनत और नवाचार के बल पर नई पहचान बना रही हैं और हमारी सरकार उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ये बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित 'लखपति दीदी संवाद' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में प्रदेशभर से आई स्व-सहायता समूह की हजारों महिलाएं और लखपति दीदियां उत्साहपूर्वक शामिल हुईं।

कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा, गुरु खुशवंत साहेब, लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक सुनील सोनी समेत बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद थीं। कार्यक्रम के दौरान इनक्यूबेशन परियोजना का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों की मदद करना है। तीन साल की परियोजना की लागत 10 करोड़ 70 लाख रखी गई है।

बिहान योजना से जुड़ने के बाद जिंदगी बदली-राजकुमारी-कार्यक्रम में दो संभाग स्तरीय FPO और एक राज्य स्तरीय लाइव स्टॉक मार्केटिंग फेडरेशन



का भी शुभारंभ किया गया। इसके जरिए महिला किसानों को बकरी पालन वैल्यू चैन के विभिन्न चरणों में शामिल करके उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान बस्तर की बेटी राजकुमारी कश्यप ने सीएम से सीधा संवाद करते हुए संघर्ष से सफलता की अपनी कहानी सुनाई। मंच पर पहुंचकर राजकुमारी कश्यप ने कहा- मैं बस्तर की बेटी हूँ, जहां कभी नक्सल का गढ़ हुआ करता था, उस समय बाइक से निकलने में भी डर लगता था, मैं घर से बाहर तक नहीं निकलती थी। बिहान योजना से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी बदली।

राजकुमारी ने बताया कि पहले वे किसी समूह से जुड़ी नहीं थीं और कुछ भी नहीं जानती थीं, लेकिन मुर्गी पालन से अपने व्यवसाय की शुरुआत की। आज वे हर महीने 35 से 40 हजार रुपये तक की कमाई कर रही हैं। इसी कमाई से उन्होंने अपने बेटे के लिए ट्यूटर भी खरीदा है। राजकुमारी कश्यप ने बताया कि आज मैं लखपति बन चुकी हूँ, आने वाले दिनों में करोड़पति बनने का सपना है।

छत्तीसगढ़ कला किताब और कॉफी टेबल बुक का हुआ विमोचन- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कॉफी टेबल बुक किताब को भी विमोचन किया। लखपति दीदियों की सफलता की कहानी इस किताब में मौजूद है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कला किताब का भी विमोचन मुख्यमंत्री ने किया। इस किताब में दीदियों के उत्पादों को बाजार में किस ढंग से बेनाया जाता है, इसका जिक्र किया गया है। इनक्यूबेशन परियोजना के शुभारंभ के साथ लखपति दीदियों का सम्मान भी मुख्यमंत्री ने किया। इसके साथ ही लखपति दीदी ग्राम पोर्टल का भी अनावरण किया गया।

अब तक 200 महतारी सदन बनकर तैयार- डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि मैं गुजरात दौरे पर गया था, वहां एक डेयरी है। डेयरी का टर्न ओवर 21 हजार करोड़ रुपए है। आगामी दिनों में उनका लक्ष्य 24 हजार करोड़ रुपए टर्नओवर करने का है। डिप्टी सीएम के अनुसार हमारे भी छत्तीसगढ़ के स्व सहायता समूह का लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए के ऊपर का होना चाहिए। अब तक 200 महतारी सदन बनकर तैयार हैं, ताकि सभी दीदियां अपना काम आसानी से कर सकें। डिप्टी सीएम ने बताया कि आने वाले समय में जैसे आप फूड ऑर्डर करते हैं, वैसे ही एक एप्लीकेशन होगा, जिसमें महिला स्व सहायता समूह की सभी सामग्री मिलेगी और उसकी घर तक डिलीवरी भी होगी।

लखपति दीदियों को करोड़पति बनाने दी जाएगी ट्रेनिंग: सीएम

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि रायपुर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उल्लेख में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम 2026 का आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ। पूरे प्रदेश की लखपति दीदियों की उपस्थिति देखी गई। लखपति दीदियों ने अपनी सफलता की कहानी भी सुनाई, उन्हें बहुत-बहुत बधाई। पूरे प्रदेश की माता- बहनों को उनसे प्रेरणा मिलेगी।

माता बहनों के साथ खड़ी है सरकार

सीएम ने कहा, सरकार माता बहनों के साथ खड़ी है। आगे भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से बकरी पालन वलस्टर योजना का शुभारंभ हुआ है। आईआईएम रायपुर के साथ सरकार ने एमओयू भी किया है, जिसके तहत अब लखपति दीदियों को करोड़पति बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि पूरे गांव की दीदियां लखपति हो गईं तो उस गांव को लखपति घोषित करने की योजना है।

विकसित छत्तीसगढ़ में लखपति दीदियों का अहम योगदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक बेटी शिक्षित होती है तो दो घर को आबाद करती है। इस योजना की शुरुआत के लिए सीएम ने पीएम मोदी को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ में लखपति दीदियों का अहम योगदान है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लखपति दीदियों के खतों में भेजे जाते हैं। सरकार माताओं- बहनों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में 8 लाख लखपति दीदियां हैं, जिन्हें बढ़ाकर दस लाख तक के करने का लक्ष्य है।

छिटी सीएम शर्मा बोले-पूरा गांव लखपति दीदी बनेगा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भारसाधक मंत्री विजय शर्मा ने अपने उद्घोष में बताया कि मुख्यमंत्री जी रोज पूछते हैं कि कितना काम हुआ है, हम उन्हें रोज का पूरा ब्यौर देते हैं कि हमने कितना काम किया है। आज छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साहस से 8 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। अब यह दीदी लखपति से करोड़पति दीदी बनने की तैयारी में है।

खेत में अफीम की खेती करने वाले विनायक को भाजपा ने किया निलंबित

रायपुर। अपने खेत में अफीम की खेती करने वाले विनायक ताम्रकार को भाजपा ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। विनायक, पार्टी के राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प का प्रदेश संयोजक था। पार्टी ने कहा कि विनायक का यह कृत्य अनुशासनहीन और छवि धूमिल करने वाला है। आपका यह कृत्य पार्टी अनुशासनहीनता करने की श्रेणी में आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव ने आपको उपरोक्त कृत्य के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बता दें कि पुलिस ने कल ही दुर्ग में शिवनाथ नदी पर समोदा में विधायक की खेत में नौ एकड़ में अफीम की फसल को बरामद किया था। यह अफीम, मक्के की फसल के बीच लगाया था। इस मामले में विनायक का बेटा भी शामिल है। फिलहाल विनायक पुलिस हिरासत में है।

भारत को अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धी देशों से बेहतर ट्रेड डील मिली

नई दिल्ली। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को अमेरिका के साथ अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर व्यापार समझौता मिला है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध बेहद मजबूत और बहुआयामी हैं। गोयल ने पहले भी यह दावा किया है। रायसीना डायलॉग में बोलते हुए गोयल ने कहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी अर्थव्यवस्था करीब 30 ट्रिलियन डॉलर की है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद सकारात्मक रहे हैं और पिछले वर्ष

के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत और नरेंद्र मोदी की सहायता की है। गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार हैं और दोनों दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। उनके अनुसार व्यापार समझौते का उद्देश्य अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर बाजार पहुंच दिलाना होता है और इस मामले में भारत को सबसे अच्छा समझौता मिला है। उन्होंने कहा कि भारत को यह बहुत अपने पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ-साथ एशिया के अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में मिली है।

कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं: साय

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 35वीं रैंक प्राप्त करने वाली वैभवी को मुख्यमंत्री ने दी बधाई

रायपुर। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 35वीं रैंक प्राप्त करने वाली सुश्री वैभवी अग्रवाल ने आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री श्री साय ने सुश्री वैभवी को मिठाई सेवाओं को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर बाजार पहुंच दिलाना होता है और इस मामले में भारत को सबसे अच्छा समझौता मिला है।

उन्होंने कहा कि भारत को यह बहुत अपने पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ-साथ एशिया के अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में मिली है।



में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वैभवी की यह सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की उपलब्धियां यह संदेश देती हैं कि लक्ष्य के प्रति समर्पण, अनुशासन और निरंतर प्रयास से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।

कलेक्टर ने यूपीएससी में 35वां स्थान प्राप्त करने वाली वैभवी का किया सम्मान

यूपीएससी 2025 में 35वां स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन करने वाली सुश्री वैभवी अग्रवाल के निवास पहुंचकर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने मिठाई खिलाकर, पुष्पगुच्छ तथा प्रेरक पुस्तक भेंट कर बधाई दी और उज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिधरंजन तथा रायपुर एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

भारत वो देश, जो किसी भी पक्ष से बात कर सकता है

वैश्विक तनाव के बीच बोले फिनलैंड के राष्ट्रपति

मुंबई (ए)। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्त्व ने शनिवार को भारत की जमकर सराहना की है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन चुनदा देशों में शामिल है, जो वैश्विक विवादों में हर पक्ष से बात कर सकता है।

उन्होंने भारत की विदेश नीति को बहुत व्यावहारिक और वास्तविक बताया। स्त्व के अनुसार, भारत की यह खूबी उसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक विशेष स्थान दिलाती है। यह बात उन्होंने



बढ़ती भू-राजनीतिक तनावों के बीच कही। राष्ट्रपति स्त्व ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मुंबई में समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र किया। स्त्व ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री के साथ तीन घंटे बिताता मेरे लिए सम्मान और

सौभाग्य की बात थी। हमने विश्व भर के संघर्षों, चीन, अमेरिका, रूस और यूरोप के साथ संबंधों के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी व्यापक और सार्थक बातचीत की। स्त्व ने कहा कि आधुनिक संघर्ष स्थानीय युद्धों से आगे बढ़कर क्षेत्रीय संकट बन गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति नाजुक है। स्त्व ने क्षेत्र में तनाव कम करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही देश झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करें, लेकिन कोई भी इसके ग्लोबल असर से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे तेल की कीमतें, व्यापार और समुद्री मार्ग हमेशा प्रभावित होते हैं।

भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति में बढ़ोतरी

भारत में 308 अरबपति, दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचा देश

नई दिल्ली (ए)। भारत में तेजी से बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और उद्योगिता के चलते अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत में अब कुल 308 अरबपति हो गए हैं। यह संख्या पिछले साल की तुलना में 24 अधिक है।

इस बढ़ोतरी के साथ ही भारत अरबपतियों की संख्या के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में भारत से आगे केवल अमेरिका और चीन हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में भारत में 57 नए अरबपति जुड़े हैं, जो अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा है। हालांकि इसी दौरान 27 लोग ऐसे भी रहे जो किसी कारणवश इस सूची से बाहर हो गए। हुरुन अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट बताती है कि



भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक साल में उनकी कुल संपत्ति करीब 10 प्रतिशत बढ़कर 112.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस दौरान 199 अरबपतियों की संपत्ति में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि 109 अरबपतियों की संपत्ति या तो घटी है या फिर उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल अरबपतियों में लगभग 7 प्रतिशत

महिलाएं हैं। मुकेश अंबानी रहे भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति- रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 9.8 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। पिछले साल की तुलना में उनकी संपत्ति में करीब 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अदानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अदानी दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। हालांकि उनकी संपत्ति में करीब 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है और अब उनकी कुल संपत्ति लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपये रह गई है। तीसरे स्थान पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मकनोत्रा हैं। उनकी संपत्ति लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपये है।

हेल्थकेयर सेक्टर से सबसे ज्यादा नए अरबपति

रिपोर्ट के अनुसार इस साल सबसे ज्यादा नए अरबपति हेल्थकेयर सेक्टर से सामने आए हैं। इस क्षेत्र से 53 नए नाम सूची में शामिल हुए। इसके बाद औद्योगिक उत्पाद क्षेत्र से 36 और उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र से 31 नए अरबपति जुड़े। हालांकि अरबपतियों की कुल संपत्ति के लिहाज से ऊर्जा क्षेत्र सबसे आगे रहा। ऊर्जा क्षेत्र के केवल आठ अरबपतियों के पास कुल 18.3 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो भारत के कुल अरबपति धन का लगभग 16 प्रतिशत हिस्सा है।

तेलंगाना में नक्सलियों का बड़ा सरेंडर

सीएम रेड्डी की मौजूदगी में 130 माओवादियों ने डाले हथियार

हैदराबाद। तेलंगाना में माओवादी संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री रेवेंत रेड्डी के सामने 31 मार्च, 2026 से पहले बड़ी संख्या में माओवादी कैडरों ने शुक्रवार आत्मसमर्पण कर दिया।

अलग-अलग स्तर के कुल 130 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें संगठन के 3 स्टेट कमेटी मेंबर, 1 रीजनल कमेटी मेंबर, 10 डिवीजनल/डीवाईसीएम स्तर के कैडर, 40 एरिया कमेटी मेंबर और करीब 70 पार्टी मेंबर शामिल बताए जा रहे हैं। आत्म समर्पण में बड़ी संख्या में बस्तर



मूल के माओवादी शामिल हैं। PLG बटालियन में सक्रिय 42, तेलंगाना स्टेट कमेटी में सक्रिय 30, डंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़े 32, 2nd सीआरसी के 16 और केंद्रीय समिति सदस्य देवजी की टीम से जुड़े 10 माओवादियों ने हिंसा का

रास्ता छोड़ा है। 130 माओवादियों पर 4.18 करोड़ रुपए का था इनाम- इन माओवादियों के ऊपर 4 करोड़ 18 लाख 20 हजार रुपए का इनाम घोषित है। आत्मसमर्पण के दौरान माओवादियों ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने भारी मात्रा में हथियार और युद्ध सामग्री भी सौंप दी। बरामद हथियारों में 1 ईसास एलएमजी, 21 AK-47, 21 ईसास रायफल, 20 एसएलआर, 18 .303 रायफल, 1 नौ एमएम कारबाइन, 2 नौ एमएम पिस्टल, 2 आठ एमएम बोल्ट-एक्शन

रायफल, 18 कट्टी मेड गन और 2 बीजीएल शामिल हैं। सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति के चलते माओवादी कैडरों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। बड़ी संख्या में हुए इस सामूहिक समर्पण को सुरक्षा एजेंसियां माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा झटका मान रही हैं। सरकार का कहना है कि जो भी उग्रवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनके लिए पुनर्वास और नई शुरुआत के सभी रास्ते खुले हैं।

सीएम ममता बनर्जी की हुंकार: धरने के दूसरे दिन कहा-

दिल्ली की सरकार दया पर टिकी ज्यादा दबाव डाला तो गिरा दूंगी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने धरना कार्यक्रम के दूसरे दिन केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा दबाव बनाया गया तो वह दिल्ली की सरकार को गिरा सकती हैं।

उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ चंद्रबाबू नायडू की दया पर तुम्हारी सरकार बनी हुई है। कोलकाता में जारी धरना मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बंगाल की जनता



को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट काटकर बंगाल को बांटने की कोशिश पहले भी की गई, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। बंगाल लड़ना जानता है और यह के लोग लोकतंत्र की रक्षा करना भी जानते हैं।

दिल्ली की सत्ता को भी चुनौती देने से पीछे नहीं

ममता बनर्जी ने केंद्र की गठबंधन राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली की मौजूदा सरकार सहयोगी दलों के सहारे टिकी हुई है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का नाम लेते हुए कहा, कुछ लोग दूसरों की दया पर टिके हुए हैं, और यदि स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो वह दिल्ली की सत्ता को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के मुँह को लेकर भी संकेतात्मक टिप्पणी की।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेष: कच्चे मकान से पक्के आशियाने तक, ग्राम उफरा की बासन बाई यादव के संघर्ष और आत्मविश्वास की प्रेरक कहानी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाज में ऐसी अनेक महिलाओं की कहानियाँ सामने आती हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से जीवन को नई दिशा दी। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी जिला बेमेतरा के ग्राम पंचायत उफरा की निवासी 70 वर्षीय श्रीमती बासन बाई यादव की है, जिनके जीवन में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने एक नया उजाला भर दिया। जिला स्तरीय महिला सम्मेलन/महिला मंडळ के अवसर पर बासन बाई यादव की कहानी इस बात का उदाहरण बनकर सामने आई कि सरकारी योजनाओं



आवास पूर्ण पक्ष

का सही लाभ मिलने पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन संभव है। वयों तक कच्चे और जर्जर मकान में जीवन बिताने वाली बासन बाई आज अपने पक्के घर में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रही हैं।

संघर्ष और कठिनाइयों से भरी जिंदगी-छत टपकती थी उसके कच्चे मकान की, फिर भी इरादा मजबूत था बासन बाई की।- ये पंक्तियाँ बासन बाई यादव के जीवन के संघर्ष और उनके मजबूत इरादों को बखूबी दर्शाती हैं। ग्राम पंचायत उफरा की रहने वाली बासन बाई यादव एक बुजुर्ग विधवा महिला हैं, जो अपनी बेटी और दामाद के साथ रहती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके पास रहने के लिए केवल एक कच्चा और जर्जर मकान ही था। घर की हालत इतनी खराब थी कि उसमें ठीक से बैठने और सोने तक की जगह नहीं होती थी। बरसात के मौसम में मकान की छत से पानी टपकता रहता था

और पूरा घर भीग जाता था। बरसात की रातें उनके लिए सबसे ज्यादा कठिन होती थीं। पानी टपकने के साथ-साथ साँप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों के घर में घुस आने का खतरा हमेशा बना रहता था। ऐसी स्थिति में पूरा परिवार डर और चिंता के बीच रात गुजारने को मजबूर था। प्रधानमंत्री आवास योजना बनी जीवन की नई उम्मीद-बासन बाई यादव के जीवन में बदलाव की शुरुआत तब हुई, जब उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत हुआ। जब उन्हें योजना की पहली किस्त प्राप्त हुई, तो उनके जीवन में नई उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्होंने तुरंत अपने पक्के घर के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। घर निर्माण में उनकी बेटी और दामाद

ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने श्रमदान करते हुए पूरे मन से घर बनाने में सहयोग दिया। निर्माण कार्य के दौरान उन्हें लगभग 90 मानव दिवस का रोजगार भी प्राप्त हुआ, जिससे परिवार को आर्थिक सहयोग भी मिला। ग्राम पंचायत और प्रशासन के सहयोग से उन्हें योजना की सभी किस्तें समय पर प्राप्त हुईं और जल्द ही उनका पक्का मकान बनकर तैयार हो गया। अब मिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास-घर का निर्माण पूर्ण होने के बाद बासन बाई यादव अपने नए पक्के मकान में रहने लगी हैं। यह मकान उनके लिए केवल एक घर नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और आत्मविश्वास की जीत का प्रतीक है। अब उन्हें बरसात में छत टपकने

की चिंता नहीं रहती और न ही साँप-बिच्छू का डर सताता है। पक्के घर ने उन्हें सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया है। बुढ़ापे में यह घर उनके लिए एक मजबूत सहारा बन गया है, जहाँ वे सुकून और गर्व के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। योजना ने लौटाई चेहरे की मुस्कान-बासन बाई यादव कहती हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके जीवन को बदल दिया है। पहले जहाँ उन्हें अपने घर की खराब स्थिति को लेकर चिंता रहती थी, वहीं आज अपने पक्के घर को देखकर उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास की चमक दिखाई देती है। उनका कहना है कि यह घर उनके लिए केवल एक आशियाना

नहीं, बल्कि जीवन भर के संघर्ष का फल है। महिला सशक्तिकरण की सशक्त मिसाल-अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बासन बाई यादव की कहानी महिला सशक्तिकरण की एक सशक्त मिसाल बनकर सामने आती है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए धैर्य और साहस के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया। आज उनकी यह कहानी न केवल गांव की महिलाओं के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह दर्शाती है कि यदि अवसर और सहयोग मिले, तो महिलाएं हर चुनौती का सामना कर अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना

(ग्रामीण) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से हजारों परिवारों को पक्का घर मिल रहा है और उनके जीवन में स्थिरता और सम्मान का नया अध्याय जुड़ रहा है। बासन बाई यादव की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब सरकारी योजनाएं सही पात्रों तक पहुंचती हैं, तो वे लोगों के जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव ला सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर बासन बाई यादव जैसी संघर्षशील महिलाओं को नमन करते हुए यह कहना उचित होगा कि उनका साहस और आत्मविश्वास समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

एक राय होकर हत्या करने कि नियत से धारदार वस्तु से मारकर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में 04 आरोपित गिरफ्तार

बेमेतरा/मूक पत्रिका

प्राथी चंदन सिंह जांगडे पिता हिरा सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी मनोधरपुर चौकी मारो थाना नांदघाट ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 05 मार्च 2026 को तेजप्रकाश उर्फ राज महिलागे, खुमेन्द्र महिलागे उर्फ कृष्णा महिलागे, डाजील महिलागे, जगदीश उर्फ जग्गी महिलागे निवासी मनोधरपुर द्वारा एक राय होकर मेरा लड़का साहिल जांगडे एवं अजय भारती का हत्या करने कि नियत से धारदार वस्तु से गर्दन, हाथ, पेट में मारकर गंभीर चोट पहुंचाया है। कि रिपोर्ट पर पुलिस चौकी मारो, थाना नांदघाट में अपराध सदर धारा 109,3(5) ब्रह्म पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देशन एवं



पिता दुलेश कुमार महिलागे उम्र 25 वर्ष, 02. खुमेन्द्र उर्फ कृष्णा महिलागे पिता दुलेश कुमार महिलागे उम्र 21 वर्ष, 03. डाजील महिलागे पिता दूजराम महिलागे उम्र 18 वर्ष,

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेमेतरा भूषण एका के मार्गदर्शन में पुलिस चौकी प्रभारी मारो उप निरीक्षक द्वारिका प्रसाद देशलहरे को चौकी स्टाफ के साथ प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में लगाया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी तेजप्रकाश उर्फ राज महिलागे, खुमेन्द्र महिलागे उर्फ कृष्णा महिलागे, डाजील महिलागे, जगदीश उर्फ जग्गी महिलागे निवासी मनोधरपुर पुलिस चौकी मारो को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना अपराध करना स्वीकार किया गया। आरोपी 01. तेज प्रकाश उर्फ राज महिलागे

04. जगदीश महिलागे उर्फ जग्गी पिता दूजराम महिलागे उम्र 20 वर्ष, निवासी मनोधरपुर, चौकी मारो थाना नांदघाट जिला बेमेतरा को दिनांक 06.03.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया। इस संपूर्ण कार्यवाही में पुलिस चौकी प्रभारी मारो उप निरीक्षक द्वारिका प्रसाद देशलहरे, प्रधान आरक्षक शत्रुहन बजारे, आरक्षक चेतन वैष्णव, बालमुकुंद सिंह, आसिफ खान, संजुनाथ योगी सहित चौकी मारो के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।

जिला मुख्यालय सारंगढ़ को विकसित करने कई स्थलों का कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने पूरी टीम के साथ किया मुआयना

इंडोर स्टेडियम, रेंजरपारा पुल और प्रस्तावित सर्किट हाउस स्थल के आसपास क्षेत्र का सफाई, सौंदर्यीकरण और अवैध कब्जा हटाने के निर्देश

मुक्तिधाम, सब्जी मार्केट और मुड़ा तालाब किनारे से अतिक्रमण हटाने और सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश पीएचई विभाग को श्मशान घाट में बोर खनन कराने के निर्देश



सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिला मुख्यालय सारंगढ़ शहर को विकसित करने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने पूरी टीम के साथ शहर के कई स्थलों का शुक्रवार को निरीक्षण कर विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया साथ ही पुलिस और राजस्व विभाग को नगरपालिका के साथ

समन्वय कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सारंगढ़ क्षेत्र के गधाभाटा रोड स्थित इंडोर स्टेडियम के पास बने कचरा डंपिंग स्थल का निरीक्षण किया, जहां साफ-सफाई का कार्य चल रहा है। उन्होंने नगरपालिका सीएमओ को निर्देश दिए कि स्थल पर मिट्टी खलकर रोलर चलाया जाए तथा आसपास की झाड़ियों की भी सफाई कराई जाए। उन्होंने एसटीपी (सीवेज

ट्रीटमेंट प्लांट) के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने की जानकारी लेते हुए जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जेलपारा और रेंजर पारा पुल के पास (पुराना नाम नाका नंबर 5) चल रहे रंग-रोगान कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तावित सर्किट हाउस के लिए स्थल का भी निरीक्षण किया। यह सर्किट हाउस करीब डेढ़ एकड़ भूमि में बनाया जाएगा, जिसके कार्य को

जल्द प्रारंभ कर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसी दौरान लोहारिन डबरी तालाब की बाउंड्रीवाल का कार्य जल्द पूरा करने के लिए नगरपालिका को निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने सारंगढ़ के मुक्तिधाम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मुक्तिधाम के सामने बनी झोपड़ियों को हटाने और आदर्श मुक्तिधाम के पास लगे अवैध ठेठों को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही

मुक्तिधाम परिसर में बाउंड्रीवाल निर्माण कराने तथा पीएचई विभाग को श्मशान घाट में बोर खनन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मुक्तिधाम परिसर में फैली गंदगी को तत्काल साफ कराने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सब्जी मार्केट का भी जायजा लिया और वहां दुकानों के शेड में हुए बेजा कब्जे को हटाने तथा पूरे बाजार क्षेत्र में साफ-सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा कमला नगर मुड़ापार वार्ड क्रमांक 11 स्थित तालाब किनारे हुए अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश भी नगरपालिका को दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि शहर की साफ-सफाई, रंगरोगन सजावट और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और निर्धारित समय में कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।

जिले की सभी ग्राम पंचायतों में मनाया गया आवास दिवस एवं रोजगार दिवस

प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा, हितग्राहियों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला बेमेतरा में प्रत्येक माह की तरह इस माह भी 7 तारीख को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आवास दिवस एवं रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा के निर्देशाुसर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और पंचायत स्तरीय अधिकारियों की सहभागिता रही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मनरेगा से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर हितग्राहियों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया गया।



को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसमें हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया, आवास की स्वीकृति, किस्तों के अंतरण तथा निर्माण कार्य की प्रगति से जुड़ी जानकारी विस्तार से साझा की गई। इसके साथ ही जिन हितग्राहियों के आवास अभी तक अधूरे हैं, उन्हें शीघ्र आवास निर्माण पूर्ण करने के लिए प्रेरित और समझाइश दी गई। वहीं जिन हितग्राहियों द्वारा अब तक आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। अन्यथा निर्धारित समय सीमा के बाद

संबंधित हितग्राहियों से स्वीकृत राशि की वसूली की कार्यवाही किए जाने की चेतावनी भी दी गई। मनरेगा से जुड़े कार्यों और भुगतान पर चर्चा-कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत चल रहे कार्यों की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। उपस्थित श्रमिकों और हितग्राहियों की मजदूरी भुगतान से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया गया तथा उन्हें योजना से मिलने वाले लाभों के बारे में अवगत कराया गया। इसके साथ ही ड्रक वरन्स से संबंधित विषयों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई और ग्रामीणों को योजना के माध्यम से अधिक से अधिक

लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। जल संरक्षण के लिए जनसहभागिता पर दिया गया जोर-बैठक के दौरान जिले में संभावित जल संकट को देखते हुए ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि भूजल स्तर को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार को अपने घरों में सोखता गड्ढा (सोक पिट) या वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण करना चाहिए। इस संबंध में ग्रामीणों से अपील की गई कि वे जनसहभागिता के माध्यम से जल संरक्षण के कार्यों को बढ़ावा दें, ताकि आने वाले समय में जल संकट की समस्या को कम किया जा सके। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में पहल-आवास दिवस एवं रोजगार दिवस के आयोजन से ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई और उन्हें अपनी समस्याओं को सीधे अधिकारियों के सामने रखने का अवसर भी मिला। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को और अधिक गति मिल सके।

सेवा सहकारी समिति बेमेतरा में मनाया गया होली मिलन समारोह

बेमेतरा/मूक पत्रिका

सेवा सहकारी समिति मर्यादित बेमेतरा प क्र 118 में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें समिति क्षेत्र के कृषक सदस्यों को गुलाल लगाकर एवं गमछा पहनाकर सम्मानित किया गया धान विक्रय करने वाले कृषकों ने शासन द्वारा कृषक उन्नति योजना में आदान सहायता राशि मिलने पर हर्ष व्यक्त किये और एक दूसरे को गुलाल लगाकर मुँह मीठ कराकर खुशी के साथ होली मिलन कार्यक्रम किये समारोह में सभी कृषक सदस्यों किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आई सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष दोहाई वर्मा व समिति प्रबंधक विनोद राजपूत के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी कार्यालय में अन्नदाता किसानों के साथ भारी खुशी उत्साह के साथ होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होने वाले में



प्रमुख रूप से किसान मोर्चा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष मोटी साहू, किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नीलू ठाकुर, विकास तम्बोली पाषंद वार्ड

11 व सभापति नगर पालिका परिषद बेमेतरा, पूर्व पाषंद वार्ड 9 साधेलाल बघेल, देवगाम साहू पूर्व पाषंद दयाराम साहू शेखर वर्मा भामू साहू फेर वर्मा दीनाराम साहू यादव राम साहू लच्छन वर्मा राजेन्द्र साहू राजीव तम्बोली बलराम देवगाम नंदलाल वर्मा सहित क्षेत्र के प्रबुद्ध किसान अधिकारी कर्मचारी गणमान्य नागरिक ग्रामवासी नगरवासी उपस्थित हुए।

सफलता कि कहानी: सपनों का घर हुआ साकार:

प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्राम अतरगंवा की उत्तरा बाई के जीवन में आया बड़ा बदलाव

बेमेतरा/मूक पत्रिका

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवारों को सुरक्षित एवं पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से हजारों परिवारों के सपने साकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत अतरगंवा की रहने वाली उत्तरा बाई की कहानी है, जिनके जीवन में इस योजना ने एक नया उजाला भर दिया है। आज से कुछ वर्ष पहले तक उत्तरा बाई का परिवार एक जर्जर और कच्चे मकान में रहने को मजबूर था। गरीबी और सीमित आय के कारण उनके लिए पक्का घर बनाना केवल एक सपना बनकर रह गया था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की मदद से यह सपना अब हकीकत में बदल गया है। संघर्ष और कठिनाइयों से भरा जीवन-जनपद पंचायत नवागढ़ से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत अतरगंवा की निवासी उत्तरा बाई (उम्र



लगभग 55 वर्ष) एक गरीब मजदूर परिवार से संबंध रखती हैं। परिवार की आय का मुख्य स्रोत मजदूरी ही था। सीमित आय में परिवार का गुजारा करना ही मुश्किल था, ऐसे में पक्का घर बनाना उनके लिए असंभव सा लगता था। उत्तरा बाई और उनका परिवार एक टूटे-पूटे कच्चे मकान में रहते थे। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था और घर की दीवारें भीग जाती थीं। कई बार घर के अंदर जगह-जगह पानी भर जाता था, जिससे रातभर ठीक से सो पाना भी मुश्किल

हो जाता था। इसके अलावा घर के आसपास की स्थिति भी सुरक्षित नहीं थी। बारिश के मौसम में साँप-बिच्छू जैसे जहरीले जीव घर के अंदर घुस आते थे, जिससे परिवार के सदस्यों को हमेशा डर और चिंता बनी रहती थी। इन कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताते हुए उत्तरा बाई अक्सर सोचती थीं कि काश उनका भी एक पक्का और सुरक्षित घर हो। पक्के घर का सपना और उम्मीद-उत्तरा बाई बताती हैं कि उन्होंने हमेशा अपने परिवार के लिए एक

सुरक्षित घर का सपना देखा था। उनका मानना था कि अगर परिवार के पास मजबूत और पक्का घर हो तो जीवन की कई परेशानियाँ अपने आप कम हो जाती हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मजदूरी से सपना साकार होना संभव नहीं लग रहा था। मजदूरी से होने वाली कमाई से केवल रोजमर्रा की जरूरतें ही पूरी हो पाती थीं। इसी बीच उन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जानकारी मिली। ग्राम सभा में पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार की गई और वर्ष 2024-25 में उत्तरा बाई का नाम भी इस योजना में स्वीकृत हो गया। योजना के सहयोग से बना नया घर-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति मिलने के बाद उत्तरा बाई के घर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों, सचिव, आवास मित्र तथा रोजगार सहायक के मार्गदर्शन में निर्माण कार्य आगे बढ़ा। प्रशासन और पंचायत के सहयोग से निर्धारित समय में घर का निर्माण कार्य पूरा किया गया। 28 मई 2025 को उत्तरा बाई का पक्का मकान बनकर तैयार हो गया। यह घर केवल ईंट और सीमेंट से बना एक भवन नहीं है, बल्कि यह उनके संघर्ष, धैर्य और

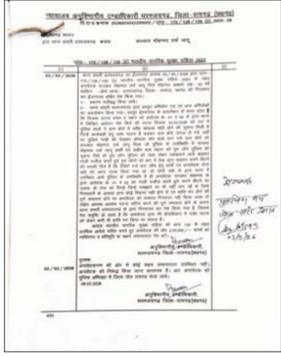
उम्मीदों की जीत का प्रतीक बन गया है। प्रेरणा बन रही है उत्तरा बाई की कहानी-उत्तरा बाई की कहानी इस बात का उदाहरण है कि जब सरकारी योजनाएं सही पात्र तक पहुंचती हैं, तो वे लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकती हैं। आज उनका पक्का घर न केवल उनके परिवार के लिए सुरक्षा और खुशी का प्रतीक है, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। यह कहानी बताती है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद उम्मीद और प्रयास से सपनों को साकार किया जा सकता है। अब बदली जिंदगी, मिला सुरक्षा और सम्मान-आज उत्तरा बाई अपने परिवार के साथ नए पक्के मकान में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब उन्हें बारिश के दिनों में घर टपकने की चिंता नहीं रहती और न ही रातभर जागकर पहरा देने की मजबूरी है। नए घर ने उन्हें सुरक्षा, सुविधा और सम्मानजनक जीवन दिया है। परिवार के सदस्य अब आराम से रह पाते हैं और बच्चों को भी सुरक्षित वातावरण मिला है। उत्तरा बाई कहती हैं कि पहले हर बारिश उनके लिए चिंता लेकर आती थी, लेकिन अब पक्के घर में रहने से उन्हें सुकून और आत्मविश्वास मिला है।

शासन-प्रशासन के प्रति आभार-उत्तरा बाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्का घर मिलने पर शासन और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि अगर यह योजना नहीं होती तो शायद उनका पक्के घर का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना ने गरीब परिवारों के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही योजना-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना से न केवल लोगों को पक्का घर मिल रहा है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि पात्र सभी हितग्राहियों को योजना का लाभ मिले और कोई भी गरीब परिवार कच्चे या जर्जर घर में रहने को मजबूर न रहे।

इस योजना से न केवल लोगों को पक्का घर मिल रहा है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि पात्र सभी हितग्राहियों को योजना का लाभ मिले और कोई भी गरीब परिवार कच्चे या जर्जर घर में रहने को मजबूर न रहे।

बोरो-संगरा के जंगलों में 'काला खेल': मशीनें जल, मगर असली माफिया अब भी बाहर

धरमजयगढ़ (रायगढ़)/मूक पत्रिका



कहने को धरमजयगढ़ क्षेत्र अपनी प्राकृतिक संपदा और घने जंगलों के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों यहां के बोरो और संगरा इलाके अवेध कोयला कारोबार की कालिख से सने नजर आ रहे हैं। जंगलों के भीतर बेखोफ माफिया भारी मशीनों से कोयला निकाल रहे हैं, जबकि जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति करते दिखाई दे रहे हैं।

हाल ही में संगरा के जंगलों में चैन माउंटन पीसी मशीन लगाकर खुलेआम कोयला उत्खनन किया जा रहा था। जब इसकी चर्चा गांव से लेकर चौक-चौराहों तक पहुंची तो पुलिस और खनिज विभाग हरकत में तो आए, लेकिन कार्रवाई कागजों तक ही सीमित नजर आई। पुलिस ने मामले को खनिज विभाग के हवाले कर पल्लू झाड़ लिया, वहीं खनिज विभाग ने पल्लू को कई दिनों तक राजस्व और

वन विभाग के बीच घुमाया। अंततः मशीन तो जव्त कर ली गई, लेकिन इस अवेध कारोबार के असली संचालक अब भी पकड़ से दूर हैं। खनिज विभाग ने बोरो क्षेत्र से करीब 54 टन कोयला जव्त कर अपनी कार्रवाई पूरी होने का दावा जरूर किया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान करती है। सूत्रों की मानें तो यह कार्रवाई महज एक ट्रेलर है। बोरो, संगरा, तेजपुर और लालमाटी जैसे

इलाकों में आज भी सैकड़ों टन अवेध कोयला डंप पड़ा हुआ है, जिसे माफिया धीरे-धीरे ठिकाने लगाने में जुटे हैं। कार्रवाई के डर से कुछ समय के लिए शांत हुए तस्कर अब रात के अंधेरे में फिर सक्रिय हो गए हैं। बाहरी इलाकों से बुलाए गए ट्रेक्टरों के माध्यम से अवेध कोयला ईंट भूँटों तक पहुंचाया जा रहा है। 3 मार्च को पुलिस द्वारा पकड़ी गई कोयला लदी ट्रेक्टर-ट्रॉली इसी अवेध नेटवर्क का प्रमाण मानी जा रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने ट्रेक्टर चालक सज्जाद मोहम्मद उर्फ जादू को पकड़कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 170/126/135(3) के तहत केवल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर मामले को शांत करने की कोशिश की है। सवाल यह उठ रहा है कि जब कोयला तस्करी का इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है तो उसके असली सरगना और खरीददार आखिर कानून की पकड़ से दूर क्यों हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर किसके संरक्षण में जंगलों के भीतर भारी मशीनें चल रही हैं। क्या संबंधित विभागों को बाकी इलाकों में पड़े सैकड़ों टन

अवेध कोयले की जानकारी नहीं है, या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई हैं। ट्रेक्टर चालक तो जेल पहुंच गया, लेकिन उस कोयले का असली मालिक और उसे खरीदने वाले ईंट भूँट संचालक अब भी बेखोफ हैं। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि धरमजयगढ़ में चल रहा यह खेल सिर्फ कोयले की चोरी नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि समय रहते बोरो, संगरा, तेजपुर और लालमाटी जैसे संवेदनशील इलाकों में सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो यह साफ हो जाएगा कि इस पूरे खेल में माफिया और तंत्र के बीच गहरी सांठगांठ है।

थाना प्रभारी के बिगड़े बोल

मामले में जानकारी लेने के लिए थाना प्रभारी सीताराम से संपर्क किया गया तो वे भड़क उठे। उन्होंने इसे हफ्ते भर पुराना मामला बताते हुए थाना स्टाफ भगत से जानकारी लेने को कहा। वहीं भगत ने भी आवाज ऊंची होने की बात कहकर मामले में ज्यादा जानकारी देने से परहेज किया।

नवलपुर मोड़ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भव्य स्वागत, युवाओं में दिखा उत्साह

बेमेतरा/नवागढ़/मूक पत्रिका



नवागढ़ (मुंगेली) दौर के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नवलपुर मोड़ पर युवाओं द्वारा भव्य और जोशीले अंदाज में स्वागत किया गया। इस अवसर पर युवा नेता हर्ष बघेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया और उनके दौर को लेकर उत्साहपूर्ण माहौल बनाया। स्वागत कार्यक्रम में युवाओं ने फूल-मालाओं और नारों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्र के कई युवा साथी मौजूद रहे, जिनमें सुभाषु ऋषि हिरवानी, विक्रान्त बघेल, हसन टंडन, कांशीराम नेताम, अनिल घृतलहरे, धनुष बघेल, राजा नेताम, खलावन नेताम, ईश्वर साहू, पतंगू नेताम, अजय बजाज, राहुल घृतलहरे, देवा तरुण गर्ग, लहरिया दिवाकर, सतोष



मंडावी, राहुल कोशल, मुकेश भाग लेंते हुए कार्यक्रम को सफ्त दिवाकर, ऊना पाटले, योगेश एवं बनाया।

सुरेन्द्र सिंह डोबर सहायता समिति जयपुर की पहल: जरूरतमंद विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए पेंशन

जयपुर/मूक पत्रिका



सुरेन्द्र सिंह डोबर सहायता समिति, जयपुर ने बड़वा (राव) समाज की विधवा एवं असहाय महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रति माह एक हजार रुपए की पेंशन देने का बौद्ध उद्योग है। समिति इस योजना की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से करने जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशवत ने बताया कि समिति के सूत्रधार भामाशाह सुरेन्द्र सिंह डोबर ने जयपुर में राजस्थान और मध्यप्रदेश के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद यह योजना शुरू करने का निर्णय लिया। यह पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए है जो कम उम्र में विधवा हो गई हैं, जिनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है

और जिन पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त कार्यकर्ता द्वारा आवेदन फॉर्म भरवाया जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाएंगी। स्थानीय दो गवाहों के हस्ताक्षर के बाद समिति द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। योजना के तहत प्रतिमाह एक हजार रुपए के हिसाब से छह माह के 6000 रुपए एकमुश्त, वर्ष में दो बार, कुल 12 हजार रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। वार्षिक पेंशन योजना के

पहले चरण में राजस्थान की 100 तथा मध्यप्रदेश की 20 जरूरतमंद महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के संचालन के लिए क्षेत्रवार 25 सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन कर उन्हें आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केकड़ी क्षेत्र के लिए रणजीत सिंह केशवत, मेवाड़ क्षेत्र के लिए उदयसिंह रायपुरिया तथा ढूंढाड़ क्षेत्र के लिए परीक्षित सिंह आसलपुर को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पहल की समाज अध्यक्ष प्रताप सिंह रम कृचामन ने सराहना करते हुए समिति का आभार व्यक्त किया।

किस्त मिली लेकिन सामग्री नहीं, ग्रामीण पूछ रहे-वैधानिक बालू आखिर मिलेगा कहाँ?

प्रधानमंत्री आवास योजना पर बालू संकट की मार

बरमकेला/मूक पत्रिका



प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को घर बनाने के लिए सरकार ने किस्त तो जारी कर दी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बिना बालू के मकान निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ गया है। बरमकेला क्षेत्र के ओडिशा सीमा से लगे सुदूर वनांचल के ग्राम पंचायत झाल, हड्डापली, जीरापाली, करनपाली, जोगनीपाली और कोकबाहल के हितग्राही पिछले करीब 20 दिनों से मकान निर्माण शुरू नहीं कर पा रहे हैं। वजह साफ है-क्षेत्र में बालू की उपलब्धता ही नहीं है। स्थिति इतनी विचित्र हो चुकी है कि बालू वही ला पा रहा है जिसके पास खुद का ट्रेक्टर है और जो रात के अंधेरे में

आखिर वैध रूप से बालू कहाँ से और कैसे मिलेगा। खनन का ठेका अब तक किसी को नहीं दिया गया है, वहीं महानदी क्षेत्र से बालू लाने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर ट्रेक्टर जव्त कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरकार की महत्वाकांक्षी आवास योजना आखिर जमीन पर कैसे पूरी होगी। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक असमंजस और अव्यवस्था के कारण योजना का लाभ लेने वाले लोग ही सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मकान निर्माण की समय-सीमा निकलती जा रही है और लाभार्थी बालू के अभाव में असहाय बने हुए हैं।

सरकार ने आवास तो दिया है लेकिन बालू के अभाव में घर कैसे बनाये? यही निवेदन है कि बालू को घर तक पहुंचने दिया जाये।

आकाश सिदार

दो महीने से घर को उजाड़ रहा हूँ, उजड़ने के बाद जब काम शुरू करने का समय आया है तो बालू नहीं मिल पा रहा। समय पर बालू मिलता तो अब तक मेरा घर बन गया होता।

दुबले साहू, झाल पंचायत

छड़ (सरिया) का रेट 5800 क्रिंटल, गिट्टी का रेट 5000 प्रति ट्रेक्टर तथा बालू 2700 रुपये प्रति ट्रेक्टर है। सरकार के द्वारा दिए गए 1 लाख 20 हजार रुपये 1 किचन और 1 रूम के लिए अर्थात् है। और पैसे कहाँ से लाऊँ इसका टेंशन ऊपर से बालू बैन लगा दिया गया

हा। अब घर क्या मिट्टी से बनाऊंगा? पास करोंगे क्या कच्चे मकान को?-

उत्तम सिदार

जिनके पास पहले से बालू है वो घर बना रहे हैं। ओडिशा से बालू के लिए कॉन्ट्रेक्ट कर रहे हैं लेकिन कई कार्पों से वहीं से भी बालू नहीं मिल पा रहा है।

भरत पटेल, झाल पंचायत

महानदी से बालू आता था, वहाँ के खनन करने वालों को पुलिस पकड़ रही है और उनके ट्रेक्टर जव्त कर रही है, जिससे हमें बालू नहीं मिल पा रहा है। हमें प्रशासन ये बताने कि वैध तरीके से बालू कहाँ मिलेगा? हमने पूछताछ किया तो पता चला कि अबतक किसी को खनन के लिए ठेका नहीं मिला है।

सम्राट पटेल, झाल पंचायत

प्रधानमंत्री आवास योजना की लॉटरी में 7 हितग्राहियों को मिला आवास



भिलाईनगर/मूक पत्रिका

नगर पालिक निगम भिलाई में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास आवंटन के लिए लॉटरी का आयोजन निगम सभागार में किया गया। इस लॉटरी में मोर मकान-मोर आस एवं मोर मकान-मोर चिन्हारी योजना के तहत निर्मित आवासों को शामिल किया गया। खुली एवं पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से कुल 07 हितग्राहियों को आवास आवंटित किया गया। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, सभापति गिखर बंदी साहू, पार्षद महेश वर्मा, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, नोडल अधिकारी सह अधीक्षक

अभियंता अजीत तिग्गा, जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता, सहायक अभियंता नितेश मेश्राम तथा उप अभियंता दीपक देवानं उपस्थित रहे। लॉटरी के माध्यम से अरुण तिवारी, घमांतिन बाई, ओमेन्द्र कोल्हाकर, वंदना शिवरामवार, पैयरी बाई, सीता बाई एवं मोहम्मद खालिक को आवास आवंटित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना है। लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की गई। आवास प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए शासन और निगम प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

राज्य स्तरीय सीनियर हॉकी स्पर्धा में रायगढ़ को मिला तीसरा स्थान, युवा खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का किया प्रदर्शन

रायगढ़/मूक पत्रिका



छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर हॉकी प्रतियोगिता में रायगढ़ जिले के युवा खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। मिली जानकारी के अनुसार चंद्रोदय कप जो की छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आयोजित एक राज्य स्तरीय सीनियर हॉकी 7वीं प्रतियोगिता है। यह टूर्नामेंट 28 फरवरी से 2 मार्च तक मिनी स्टेडियम, कॉलेज रोड, महासमुंद में आयोजित किया गया था। इसमें राज्य की प्रमुख हॉकी टीमों ने हिस्सा लिया था। इस मुकाबले में पहले प्राइस बिलासपुर अकेडमी और दूसरे स्थान जाजगीर और तीसरा स्थान रायगढ़ की टीम रही। रायगढ़ जिले के युवा खिलाड़ियों ने अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए राजनांदांव की

टीम को 5-2 से करारी शिकस्त देते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में रायगढ़ की टीम के कप्तान रविन्द्र यादव ने 1 गोल मारा, जबकि लालजीत मिंज 2 गोल, मदन मन्ना 1 गोल के अलावा नरेश लकड़ ने भी 1 गोल मारते हुए जीत हासिल करने में अपनी महत्वपूर्ण

भूमिका निभाई है। रायगढ़ की टीम में बेस्ट डिफेंडर के रूप में शोभित कुजूर, मनोज कुजूर, विकास केरकेट्टा, दिव्यप्रकाश मिंज, मनोज कुजूर के अलावा गोलकीपर के रूप में अजय कुजूर रहे। इस टीम के कोच अधिपेक मिंज के अलावा मैनेजर के रूप में अमृत चौहान थे।

घरघोड़ा जनपद में अधिकारी चुस्त, सचिव सुस्त.. सुस्त सचिव को दो पंचायतों का प्रभार सवालियों के घेरे में

घरघोड़ा/मूक पत्रिका



जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों में सचिवों की लापरवाही से ग्रामीणों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। आरोप है कि अधिकांश पंचायतों में सचिव अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं हैं, बावजूद इसके कई सचिवों को एक साथ दो-दो पंचायतों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिससे व्यवस्थाएं और अधिक प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायतों में सूचना के अधिकार (रजलूट) को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आवेदन देने और निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इतना ही नहीं, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जानकारी देने के आदेश के बाद भी संबंधित सचिव द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत

अनियमितताएं या भ्रष्टाचार छिपा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अपीलीय अधिकारी और जनपद पंचायत के

पोरडा और बरौद का सामने आया है, जहां सचिव शांति पैकरा को दोनों पंचायतों का प्रभार दिया गया है। आरोप है कि आरटीआई आवेदन के बाद सचिव द्वारा जानकारी देने के लिए भुगतान की मांग की गई थी। आवेदक ने नियमानुसार भुगतान भी किया, लेकिन इसके बावजूद जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जानकारी नहीं मिलने पर आवेदक ने प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश जारी होने के बाद भी सचिव द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि पंचायतों में कहीं न कहीं बड़े स्तर पर

सीईओ के आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है, तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं शांति पैकरा को बरौद के सचिव पद पर दिया गया है। एक ही सचिव को दो-दो पंचायतों का प्रभार दिए जाने को लेकर भी चर्चा तेज है। ग्रामीणों का मानना है कि इसके पीछे या तो बड़ा भ्रष्टाचार है या फिर किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

मनरेगा के माध्यम से रोजगार और आय के नए अवसर

विश्व महिला दिवस विशेष: आजीविका गतिविधियों से आत्मनिर्भर बन रही हैं जिले की महिलाएं



बेमेतरा/मूक पत्रिका

विश्व महिला दिवस के अवसर पर जिले में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न आजीविका आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्थायी आय के अवसर उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत फर्म पॉण्ड (आजीविका तालाब), मत्स्य पालन तथा कृषि आधारित अन्य गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले में महिलाओं की

सक्रिय भागीदारी के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं द्वारा 15,42,107 मानव दिवस का रोजगार प्राप्त किया गया है, जो कि जिले में सृजित कुल मानव दिवस का लगभग 52.27 प्रतिशत है। यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत देता है।

उपस्थित श्रमिकों को क्यूआर कोड आधारित उपस्थिति प्रणाली, मनरेगा श्रम भुगतान व्यवस्था, वीबी ग्रामजी सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई, ताकि श्रमिकों को योजना से जुड़ी सुविधाओं और प्रक्रियाओं के बारे में बेहतर समझ मिल सके।

सफलता की कहानी: आजीविका डबरी से बढ़ी आय-मनरेगा के अंतर्गत जिले में कई महिलाएं आजीविका गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम पंचायत अधियारखोर की भानमती (पति डू आशाराम) हैं। भानमती द्वारा मनरेगा के अंतर्गत आजीविका डबरी (फर्म पॉण्ड) का निर्माण

कराया गया। इस डबरी में वे मत्स्य पालन का कार्य कर रही हैं, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये से अधिक की आय प्राप्त हो रही है। इसके अलावा डबरी के आसपास की भूमि में वे सब्जी उत्पादन भी कर रही हैं, जिससे उनके परिवार की आय में और वृद्धि हुई है। इस गतिविधि से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि परिवार के जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आया है।

आजीविका गतिविधियों से मिल रहे रोजगार के अवसर-फर्म पॉण्ड, मत्स्य पालन और कृषि आधारित अन्य गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। कई महिला स्व-सहायता समूह भी इन गतिविधियों से जुड़कर मत्स्य पालन, सब्जी

उत्पादन और अन्य आजीविका कार्यों के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। इन पहलों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं अब स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बन रही हैं।

महिलाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण और मार्गदर्शन-जिला पंचायत के अनुसार शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। फर्म पॉण्ड और मत्स्य पालन जैसे कार्य जल संरक्षण के साथ-साथ महिलाओं की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिलाओं को इन गतिविधियों से जोड़ने के लिए उन्हें प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन तथा आवश्यक सहयोग भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे इन कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें।

महिला दिवस अवसर पर जल संरक्षण महाअभियान के रूप में बनाया जायेगा-विश्व महिला दिवस के अवसर पर जिला बेमेतरा में जल संरक्षण महाअभियान चलाने का भी निर्णय

संपादकीय

युद्ध के बीच भारतीयों को वापस लाना चिंता का विषय

ईरान पर इजरायल और अमेरिका के साझा हमले के बाद युद्ध का स्वरूप ब्रिगडिगा जा रहा है और कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में यह कौन-सी दिशा अखिरकार करेगा। खासतौर पर हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उसमें मध्य-पूर्व के देशों में भी स्थिति चिंताजनक हो रही है। ईरान के लिए एक बड़ी फिज़र यह खड़ी हुई है कि अलग-अलग उद्देश्य से मध्य-पूर्व के देशों में गए जो भारतीय फंस गए हैं, उन्हें वहां से सुरक्षित कैसे निकाला जाए। अमेरिका और इजरायल के साझा हमले के जवाब में ईरान ने इजरायल को निशाना

बनाने के साथ-साथ बहरीन, सऊदी अरब, कतर समेत कई देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल से हमले किए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि वहां रहने वाले लोगों के सामने किस तरह की मुश्किलें खड़ी हो रही होंगी। स्वाभाविक ही भारत के सामने बड़ी चिंता उन इलाकों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की है। दरअसल, मध्य-पूर्व पश्चिम एशिया का इलाका इस समय युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया लग रहा है। स्वाभाविक ही वहां रहे तमाम आम लोगों के सामने खुद को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर, जो लोग दूसरे देशों से वहां गए हैं, वे किसी तरह वहां से निकलने की उम्मीद में हैं। ऐसे में भारत सरकार ने युद्ध प्रभावित

देशों से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कोशिश शुरू की है, लेकिन ठोस नतीजे के लिए समय रहते कदम उठाना जरूरी है। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) ने पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात की समीक्षा की और सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे घटनाक्रम से प्रभावित भारतीयों की सहायता के लिए जरूरी और व्यावहारिक कदम उठाएं। सरकार की ओर से आश्चर्य किया गया है कि युद्ध के असर से जुड़े देशों में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित भारतीय दूतावासों से बातचीत की गई है। भारत ने शांति और सुरक्षा के साथ-साथ विवादों के समाधान के लिए संवाद तथा

कूटनीति का समर्थन किया है, लेकिन फिलहाल ज्यादा जरूरत इस बात की है कि युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाए। गौरतलब है कि ईरान में करीब दस हजार भारतीय नागरिक रहते हैं, जो पढ़ाई और काम करते हैं। वहीं इजरायल में चालीस हजार से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इसके अलावा, खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया में लगभग नब्बे लाख भारतीय रहते हैं। इन देशों में सैन्य तनाव बढ़ने और युद्ध का दायरा फैलने की वजह से उद्घान सेवाएं व्यापक पैमाने पर बाधित हुई हैं और बहुत सारे वैसे भारतीय उन जगहों के हवाईअड्डों पर फंसे हुए हैं, जो किसी तरह वतन लौटना चाहते हैं।

यह मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है; यह उस निरंतर मानसिक और सामाजिक दबाव से बाहर निकलने का प्रयास है जिसमें हर व्यक्ति को हर विषय पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है। आज का युवा, जो दिन भर संदेशों, सूचनाओं, टिप्पणियों और दृश्य सामग्री के प्रवाह में डूबा रहता है, पहली बार यह अनुभव कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी थकान श्रम से नहीं, बल्कि निरंतर अभिव्यक्ति की बाध्यता से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि ध्यान-शिविरों, साइलेंट-रिट्रीट, डिजिटल डिटॉक्स और एकांत यात्राओं की ओर उसका आकर्षण बढ़ रहा है। यह पलायन नहीं अपितु प्रतिरोध है।

तया मध्य-पूर्व एक और 'महायुद्ध' की दहलीज पर है?

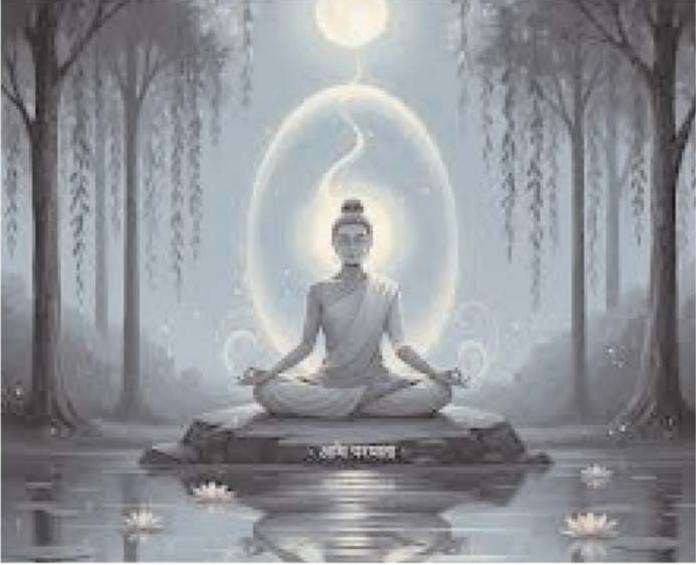
(पुष्करज)
अगर यह लड़ाई लंबी खिंचती है, तो यह खाड़ी देशों के लिए एक असली बदलाव बिंदु बन सकती है। एक ऐसा मोड़, जो देशों की सुरक्षा, उभयपक्षीय सहयोग और यहां तक कि उनके लंबे समय के आर्थिक भविष्य के बारे में सोचने के तरीके को बदल देगा।
ईरान पर अमेरिका-इजरायल के व्यापक हमले को दो दिन हुए हैं, यह पहले से ही साफ है कि इसका मध्य-पूर्व और खासकर खाड़ी पर गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका-इजरायल की बमबारी में कई बड़े अधिकारियों के साथ सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और उनके परिवार के लोग भी मारे गए हैं। ईरान में 40 दिन का शोक है। तेहरान ने न सिर्फ इजरायल बल्कि इस इलाके के कई देशों पर हमले करके जवाब दिया है।
सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और ओमान सभी पर ईरानी मिसाइलों या ड्रोन से हमला किया गया, जबकि इनमें से किसी भी देश ने अपने इलाके से ईरान पर हमला नहीं किया था। इन देशों में कई जगहों को निशाना बनाया गया, जिनमें अमेरिकी सैन्य अड्डे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और वाणिज्यिक इलाके भी शामिल थे।
अगर यह लड़ाई लंबी खिंचती है, तो यह खाड़ी देशों के लिए एक असली बदलाव बिंदु बन सकती है। एक ऐसा मोड़, जो देशों की सुरक्षा, उभयपक्षीय सहयोग और यहां तक कि उनके लंबे समय के आर्थिक भविष्य के बारे में सोचने के तरीके को बदल देगा। ईरान से जुड़ा कोई भी लंबा संघर्ष समुद्री यातायात को प्रभावित करेगा, खासकर होर्मुज की खाड़ी, जो दुनिया की आर्थिक धमनियां में से एक है। थोड़ी बहुत रुकावट से ऊर्जा की कीमते तेज हो जाएंगी, जो निवेशकों के लिए नई चिंता पैदा कर सकती है।
हां, तेल की ज्यादा कीमतें अल्पकालिक राजस्व को बढ़ा सकती हैं, फिर भी ऊर्जा बाजार असंतुलित हो जाएगा। क्या ट्रंप तेल की कीमतों में भी उछाल चाहते थे? चीन और रूस ज्यादा देर चुपचाप नहीं रहेंगे। मार्को यदि सौदा नहीं भी कृदा, मगर इस उछल-पुछल का फायदा उठाकर हथियारों की बिक्री बढ़ा सकता है,

मौन का पुनर्जन्म- शोर के युग में चुप रहने का आध्यात्मिक प्रतिरोध

(अनन्या मिश्रा)
डिजिटल दबाव और निरंतर अभिव्यक्ति से थकान बढ़ी है। युवा ध्यान, साइलेंट रिट्रीट और मौन की ओर आकर्षित हैं। मौन मानसिक संतुलन, आंतरिक अनुभव, सांस्कृतिक प्रतिरोध और अस्तित्व की वास्तविक अनुभूति प्रदान करता है।
हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बोलना केवल संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि अस्तित्व का प्रमाण बन गया है। यदि हम सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट नहीं कर रहे, यदि हम किसी चर्चा में अपनी राय व्यक्त नहीं कर रहे, यदि हमारी उपस्थिति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई नहीं दे रही, तो मानो हम धीरे-धीरे अदृश्य होते जा रहे हैं। निरंतर अभिव्यक्ति की यह संस्कृति इतनी गहराई से हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है कि चुप रहना अब स्वाभाविक नहीं, बल्कि असामान्य प्रतीत होता है। परंतु इसी असामान्यता के भीतर एक नई आध्यात्मिक प्रवृत्ति जन्म ले रही है जो है मौन का पुनर्जन्म।
यह मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है; यह उस निरंतर मानसिक और सामाजिक दबाव से बाहर निकलने का प्रयास है जिसमें हर व्यक्ति को हर विषय पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है। आज का युवा, जो दिन भर संदेशों, सूचनाओं, टिप्पणियों और दृश्य सामग्री के प्रवाह में डूबा रहता है, पहली बार यह अनुभव कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी थकान श्रम से नहीं, बल्कि निरंतर अभिव्यक्ति की बाध्यता से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि ध्यान-शिविरों, साइलेंट-रिट्रीट, डिजिटल डिटॉक्स और एकांत यात्राओं की ओर उसका आकर्षण बढ़ रहा है। यह पलायन नहीं अपितु प्रतिरोध है।
मौन का यह नया आकर्षण भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के लिए नया नहीं है, परंतु इसका संदर्भ नया है। उपनिषदों में कहा गया है कि अंतिम सत्य शब्दों से परे है - यतो वाचो निवर्तते- जहाँ वाणी लौट आती है। दक्षिणामूर्ति की प्रतिमा में गुरु मौन रहकर शिष्यों को ज्ञान देते हैं, और यह मौन ही सर्वोच्च उपदेश माना गया है। परंतु उस समय मौन साधना का मार्ग था; आज मौन मानसिक संतुलन की आवश्यकता बन गया है।
जीवन का आंतरिक आयाम धीरे-धीरे क्षीण होने लगाता है डिजिटल संस्कृति ने अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाया है, परंतु साथ ही उसने एक ऐसी अदृश्य बाधिता भी उत्पन्न की है जिसमें हर व्यक्ति स्वयं को निरंतर प्रस्तुत करने के लिए बाध्य महसूस करता है। विचार अभी पूर्ण रूप से बन भी नहीं पाता कि उसे साझा करने का दबाव उत्पन्न हो जाता है। अनुभव अभी भीतर उतर

भी नहीं पाता कि उसका दृश्य रूप तैयार कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जीवन का आंतरिक आयाम धीरे-धीरे क्षीण होने लगता है। मौन की ओर लौटना इस क्षरण के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मौन केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि तंत्रिका-तंत्र की पुनर्स्थापना का माध्यम है। निरंतर

संरचना का हिस्सा बनते हैं। मौन और ऑफलाइन समय इस अर्धव्यवस्था के प्रवाह को तोड़ते हैं। इस दृष्टि से मौन केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतिरोध भी है। परंतु यह मौन केवल बाहरी नहीं हो सकता। केवल शब्दों को रोक देना पर्याप्त नहीं, क्योंकि भीतर विचारों का शोर चलता रहता है। वास्तविक मौन तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति स्वयं को निरंतर परिभाषित करने की आवश्यकता से मुक्त होने लगता है। जब वह कुछ समय के लिए यह भूल जाता है कि उसे कौन-सा रूप प्रस्तुत करना है, तब वह अपने उस स्वरूप के निकट पहुँचता है जो किसी प्रदर्शन का विषय नहीं है। नई पीढ़ी के लिए यह अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह ऐसी दुनिया में बड़ी हुई है जहाँ पहचान को निरंतर प्रदर्शित करना पड़ता है। मौन उसे पहली बार यह अनुभव कराता है कि उसका अस्तित्व उसकी अभिव्यक्ति से बड़ा है। यह अनुभव आध्यात्मिक है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी आंतरिक उपस्थिति से जोड़ता है। मौन का पुनर्जन्म इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें संवाद की एक नई गुणवत्ता की ओर ले जा सकता है। जब शब्द कम होते हैं, तब दबाव नहीं होता, तब अनुभव अधिक स्पष्ट होता है। जब व्यक्ति स्वयं से मिलने लगता है, तब उसका संबंध दूसरों से भी अधिक प्रामाणिक हो जाता है। आज जब वर्ष का अधिकांश समय शोर, गति और निरंतर गतिविधि में बीत जाता है, तब यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या हम कभी सच में अपने साथ अकेले होते हैं। शायद मौन की ओर लौटने की यह प्रवृत्ति हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन का सबसे गहरा आयाम अभिव्यक्ति में नहीं, बल्कि उपस्थिति में है। और संभवतः यही कारण है कि नई पीढ़ी, जो सबसे अधिक बोलने वाली पीढ़ी मानी जाती है, अब चुप रहने की कला को फिर से खोज रही है। यह लेखक के निजी विचार हैं।



सूचना-प्रवाह और प्रतिक्रिया की अपेक्षा मस्तिष्क को सतत सक्रिय अवस्था में रखती है, जिससे चिंता, थकान और ध्यान-भंग की समस्या बढ़ती है। जब व्यक्ति कुछ समय के लिए भी बोलना और सुनना बंद करता है, तब वह पहली बार अपने भीतर चल रही सूक्ष्म गतिविधियों को अनुभव कर पाता है। मौन उसे यह अवसर देता है कि वह प्रतिक्रिया के स्थान पर साक्षी भाव में स्थित

नई जीवन-दृष्टि के संकेत हैं जिसमें व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं, भीतर केंद्रित करना चाहता है। क्योंकि भीतर विचारों का शोर चलता रहता है मौन का यह पुनर्जन्म एक और स्तर पर भी महत्वपूर्ण है कि यह उपभोक्तावादी संरचना के विरुद्ध खड़ा होता है। आधुनिक अर्धव्यवस्था ध्यान पर आधारित है ङ्क यानि जितना अधिक समय हम स्क्रीन पर बिताते हैं, उतना ही हम इस

संरचना का हिस्सा बनते हैं। मौन और ऑफलाइन समय इस अर्धव्यवस्था के प्रवाह को तोड़ते हैं। इस दृष्टि से मौन केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतिरोध भी है। परंतु यह मौन केवल बाहरी नहीं हो सकता। केवल शब्दों को रोक देना पर्याप्त नहीं, क्योंकि भीतर विचारों का शोर चलता रहता है। वास्तविक मौन तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति स्वयं को निरंतर परिभाषित करने की आवश्यकता से मुक्त होने लगता है। जब वह कुछ समय के लिए यह भूल जाता है कि उसे कौन-सा रूप प्रस्तुत करना है, तब वह अपने उस स्वरूप के निकट पहुँचता है जो किसी प्रदर्शन का विषय नहीं है। नई पीढ़ी के लिए यह अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह ऐसी दुनिया में बड़ी हुई है जहाँ पहचान को निरंतर प्रदर्शित करना पड़ता है। मौन उसे पहली बार यह अनुभव कराता है कि उसका अस्तित्व उसकी अभिव्यक्ति से बड़ा है। यह अनुभव आध्यात्मिक है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी आंतरिक उपस्थिति से जोड़ता है। मौन का पुनर्जन्म इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें संवाद की एक नई गुणवत्ता की ओर ले जा सकता है। जब शब्द कम होते हैं, तब दबाव नहीं होता, तब अनुभव अधिक स्पष्ट होता है। जब व्यक्ति स्वयं से मिलने लगता है, तब उसका संबंध दूसरों से भी अधिक प्रामाणिक हो जाता है। आज जब वर्ष का अधिकांश समय शोर, गति और निरंतर गतिविधि में बीत जाता है, तब यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या हम कभी सच में अपने साथ अकेले होते हैं। शायद मौन की ओर लौटने की यह प्रवृत्ति हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन का सबसे गहरा आयाम अभिव्यक्ति में नहीं, बल्कि उपस्थिति में है। और संभवतः यही कारण है कि नई पीढ़ी, जो सबसे अधिक बोलने वाली पीढ़ी मानी जाती है, अब चुप रहने की कला को फिर से खोज रही है। यह लेखक के निजी विचार हैं।

शिक्षण संस्थानों की जवाबदेही और पाठ्यक्रम विवाद

(डॉ. अमरेंद्र कुमार पाण्डेय)
हाल के समय में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में भ्रष्टाचार संबंधी उल्लेख को लेकर उत्पन्न विवाद ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और उत्तरदायित्व पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।
इस प्रकरण में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजांन लिया जाना तथा केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण माँगा जाना यह संकेत करता है कि पाठ्यक्रम निर्माण अब केवल शैक्षणिक प्रक्रिया भर नहीं रह गया है, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं और संस्थागत संतुलन से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय बन चुका है।
मूल प्रश्न न्यायपालिका की आलोचना का नहीं, बल्कि उसकी प्रस्तुति की संतुलित संरचना का है। लोकतंत्र में किसी भी संस्था की आलोचनात्मक समीक्षा स्वाभाविक और आवश्यक है; किंतु जब प्रस्तुति एकांगी हो, संदर्भ अपूर्ण हों और विद्यार्थियों की आयु-संबंधी संवेदनशीलता की उपेक्षा की जाए, तब समस्या उत्पन्न होती है।
कक्षा आठ के विद्यार्थियों के समक्ष यदि न्यायपालिका को भ्रष्टाचार के उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके साथ उसकी संवैधानिक भूमिका, नागरिक अधिकारों की रक्षा में योगदान तथा सुधारात्मक प्रयासों का उल्लेख भी अनिवार्य है। अन्यथा आलोचना शिक्षण का उपकरण न रहकर पूर्वाग्रह-निर्माण का माध्यम बन सकती है।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इस विमर्श को और गहराई प्रदान करता है। सन् 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर गंभीर प्रश्न उठे थे। विशेषकर 'जिला दंडाधिकारी जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला' प्रकरण में दिए गए निर्णय की व्यापक आलोचना हुई।
यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका भी त्रुटिहीन नहीं है और उसकी समीक्षा संभव है। किंतु समय के साथ न्यायपालिका ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की और अपनी संस्थागत विश्वसनीयता को सुदृढ़ किया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आलोचना का स्वर संतुलित ऐतिहासिक संदर्भ के साथ होना चाहिए।

मूल प्रश्न न्यायपालिका की आलोचना का नहीं, बल्कि उसकी प्रस्तुति की संतुलित संरचना का है। लोकतंत्र में किसी भी संस्था की आलोचनात्मक समीक्षा स्वाभाविक और आवश्यक है; किंतु जब प्रस्तुति एकांगी हो, संदर्भ अपूर्ण हों और विद्यार्थियों की आयु-संबंधी संवेदनशीलता की उपेक्षा की जाए, तब समस्या उत्पन्न होती है।
कक्षा आठ के विद्यार्थियों के समक्ष यदि न्यायपालिका को भ्रष्टाचार के उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके साथ उसकी संवैधानिक भूमिका, नागरिक अधिकारों की रक्षा में योगदान तथा सुधारात्मक प्रयासों का उल्लेख भी अनिवार्य है। अन्यथा आलोचना शिक्षण का उपकरण न रहकर पूर्वाग्रह-निर्माण का माध्यम बन सकती है।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इस विमर्श को और गहराई प्रदान करता है। सन् 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर गंभीर प्रश्न उठे थे। विशेषकर 'जिला दंडाधिकारी जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला' प्रकरण में दिए गए निर्णय की व्यापक आलोचना हुई।
यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका भी त्रुटिहीन नहीं है और उसकी समीक्षा संभव है। किंतु समय के साथ न्यायपालिका ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की और अपनी संस्थागत विश्वसनीयता को सुदृढ़ किया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आलोचना का स्वर संतुलित ऐतिहासिक संदर्भ के साथ होना चाहिए।

मूल प्रश्न न्यायपालिका की आलोचना का नहीं, बल्कि उसकी प्रस्तुति की संतुलित संरचना का है। लोकतंत्र में किसी भी संस्था की आलोचनात्मक समीक्षा स्वाभाविक और आवश्यक है; किंतु जब प्रस्तुति एकांगी हो, संदर्भ अपूर्ण हों और विद्यार्थियों की आयु-संबंधी संवेदनशीलता की उपेक्षा की जाए, तब समस्या उत्पन्न होती है।
कक्षा आठ के विद्यार्थियों के समक्ष यदि न्यायपालिका को भ्रष्टाचार के उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके साथ उसकी संवैधानिक भूमिका, नागरिक अधिकारों की रक्षा में योगदान तथा सुधारात्मक प्रयासों का उल्लेख भी अनिवार्य है। अन्यथा आलोचना शिक्षण का उपकरण न रहकर पूर्वाग्रह-निर्माण का माध्यम बन सकती है।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इस विमर्श को और गहराई प्रदान करता है। सन् 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर गंभीर प्रश्न उठे थे। विशेषकर 'जिला दंडाधिकारी जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला' प्रकरण में दिए गए निर्णय की व्यापक आलोचना हुई।
यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका भी त्रुटिहीन नहीं है और उसकी समीक्षा संभव है। किंतु समय के साथ न्यायपालिका ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की और अपनी संस्थागत विश्वसनीयता को सुदृढ़ किया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आलोचना का स्वर संतुलित ऐतिहासिक संदर्भ के साथ होना चाहिए।

मूल प्रश्न न्यायपालिका की आलोचना का नहीं, बल्कि उसकी प्रस्तुति की संतुलित संरचना का है। लोकतंत्र में किसी भी संस्था की आलोचनात्मक समीक्षा स्वाभाविक और आवश्यक है; किंतु जब प्रस्तुति एकांगी हो, संदर्भ अपूर्ण हों और विद्यार्थियों की आयु-संबंधी संवेदनशीलता की उपेक्षा की जाए, तब समस्या उत्पन्न होती है।
कक्षा आठ के विद्यार्थियों के समक्ष यदि न्यायपालिका को भ्रष्टाचार के उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके साथ उसकी संवैधानिक भूमिका, नागरिक अधिकारों की रक्षा में योगदान तथा सुधारात्मक प्रयासों का उल्लेख भी अनिवार्य है। अन्यथा आलोचना शिक्षण का उपकरण न रहकर पूर्वाग्रह-निर्माण का माध्यम बन सकती है।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इस विमर्श को और गहराई प्रदान करता है। सन् 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर गंभीर प्रश्न उठे थे। विशेषकर 'जिला दंडाधिकारी जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला' प्रकरण में दिए गए निर्णय की व्यापक आलोचना हुई।
यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका भी त्रुटिहीन नहीं है और उसकी समीक्षा संभव है। किंतु समय के साथ न्यायपालिका ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की और अपनी संस्थागत विश्वसनीयता को सुदृढ़ किया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आलोचना का स्वर संतुलित ऐतिहासिक संदर्भ के साथ होना चाहिए।



किसी शोरावस्था में निर्मित धारणाएँ दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ती हैं। यदि किसी एक संस्था की छवि केवल नकारात्मक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, तो विद्यार्थियों के मन में व्यापक संस्थागत अविश्वास जन्म ले सकता है। यहाँ यह प्रश्न भी विचारणीय है कि यदि न्यायपालिका को लेकर संशय उत्पन्न होता है, तो क्या विद्यार्थियों के मन में कार्यालिका के आचरण और कार्यशैली को लेकर भी प्रश्न नहीं उठेंगे?

सोमार्ण और जवाबदेही को संतुलित दृष्टि से देख सकें।
उच्च शिक्षा के स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल दिशा-निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन तथा सतत निगरानी भी आवश्यक है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को अनेक विश्वविद्यालयों ने अपनाया है; किंतु व्यवहारिक स्तर पर चौधे वर्ष की संरचना, शोध की गुणवत्ता तथा शैक्षणिक अनुशासन को लेकर प्रश्न उठे हैं। यदि नीतियों के क्रियान्वयन में स्पष्टता और कठोरता का अभाव रहेगा, तो सुधार की प्रक्रिया औपचारिकता तक सीमित रह सकती है।
पाठ्यक्रम विवादों का इतिहास भी नया नहीं है। सन् 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा लागू किए जाने के पश्चात इतिहास और सामाजिक विज्ञान की सामग्री को लेकर व्यापक बहस हुई थी।
विभिन्न समूहों ने वैचारिक संतुलन और निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम निर्माण एक संवेदनशील और बहुस्तरीय प्रक्रिया है, जिसमें पारदर्शिता, विशेषज्ञता और उत्तरदायित्व-इन तीनों का समन्वय अनिवार्य है।
इस विषय पर देश के नेतृत्व द्वारा गंभीरता व्यक्त किया जाना शिक्षा तंत्र की व्यापक जवाबदेही की ओर संकेत करता है। जब यह प्रश्न उठता है कि पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा और निगरानी किस स्तर पर होती है, तो यह केवल एक संस्था की चर्चा नहीं रह

जाती, बल्कि संपूर्ण शैक्षिक संरचना की पारदर्शिता से जुड़ जाती है। शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक आधार-निर्माण की प्रक्रिया भी है।
अतः आवश्यक है कि मतभेदों और बहसों को संस्थागत सुधार के अवसर के रूप में देखा जाए। पारदर्शी समीक्षा-तंत्र, उत्तरदायी विशेषज्ञ समितियाँ और प्रभावी निगरानी-व्यवस्था शिक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बना सकती हैं।
निष्कर्षतः शिक्षा व्यवस्था में सुधार अपरिहार्य है, परंतु वह संतुलन, पारदर्शिता और स्पष्ट जवाबदेही पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम केवल तथ्यों का संकलन नहीं, बल्कि दृष्टिकोण-निर्माण का माध्यम है।
यदि इसमें असंतुलन होगा, तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों की लोकतांत्रिक समझ पर पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि शैक्षिक संस्थाओं और संबंधित प्राधिकरणों के बीच समन्वित तथा उत्तरदायी तंत्र स्थापित किया जाए।
बच्चों का विश्वास उनकी बुनियादी शिक्षा व्यवस्था, उसकी पाठ्य-सामग्री और वहाँ अध्यापन करने वाले शिक्षकों पर आधारित होता है। यदि यह विश्वास सुदृढ़ और सकारात्मक बना रहता है, तो वही राष्ट्र की स्थायी प्रगति का आधार बनता है।
भारत भी शिक्षा में सुधार, अनुशासन और उत्तरदायित्व के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। यही हमारी सांस्कृतिक तथा सामाजिक मजबूती का वास्तविक आधार है। यह लेखक के निजी विचार हैं।

किसी शोरावस्था में निर्मित धारणाएँ दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ती हैं। यदि किसी एक संस्था की छवि केवल नकारात्मक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, तो विद्यार्थियों के मन में व्यापक संस्थागत अविश्वास जन्म ले सकता है। यहाँ यह प्रश्न भी विचारणीय है कि यदि न्यायपालिका को लेकर संशय उत्पन्न होता है, तो क्या विद्यार्थियों के मन में कार्यालिका के आचरण और कार्यशैली को लेकर भी प्रश्न नहीं उठेंगे?

एक लाख जल संरचनाओं को बचाने कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने किया जल संगवारी अभियान का समीक्षा

अब तक 24 हजार सोखता गड्डों एवं जल संरचनाओं का निर्माण जल शक्ति जन भागीदारी 2.0 पोर्टल में 16 हजार से अधिक जल संचयों की हुई एंटी



संगवारी अभियान के तहत जिलेभर में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बनाए जा रहे सोखता गड्डों, जल संरचनाओं एवं जल शक्ति-जन भागीदारी 2.0 पोर्टल में एंटी के संबंध में वन विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, उपसंचालक कृषि, कार्यपालन अभियंता पीएचई, सहायक संचालक उद्यान, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,

सीएमओ नगरपालिका सारंगढ़ आदि अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिलेभर में जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चलाए जा रहे जल संगवारी अभियान के अंतर्गत जनभागीदारी एवं योजनाओं के माध्यम से किए गए गड्डे व जल संरचनाओं के निर्माण एवं जल शक्ति पोर्टल में अब हुए एंटी के संबंध में जानकारी लेकर कलेक्टर कन्नौजे ने अप्सरों को निर्देशित किया कि जल संगवारी अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत में विभागों के माध्यम से जल बचाव हेतु आवश्यक कदम उठाये जाए,

जिसमें कालेज एवं स्कूलों में निबंध एवं पेंटिंग प्रतियोगिता, गांवों में रैली निकालकर व चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को जल निकासी स्थान पर श्रमदान से अधिक से अधिक सोखता गड्डा किए जाने प्रेरित करना आदि जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा सकते हैं। इस अवसर पर कलेक्टर ने कृषि विभाग के अमला को धान के बदले कम पानी से अधिक आमदनी वाले अन्य फसल जैसे- दलहन- तिलहन एवं मोटा फसल के उत्पादन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने निर्देशित किया, ताकि अधिक से अधिक पानी का

बचाव हो सके। उल्लेखनीय है कि जल संवर्धन हेतु कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के मार्गदर्शन में चलाये जा रहे इस अभियान के तहत जिलेभर में अब तक 24 हजार से अधिक सोखता गड्डों एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण एवं जल शक्ति जन भागीदारी 2.0 पोर्टल में 16 हजार से अधिक जल संचयों की फोटो अपलोड किया जा चुका है।

विभागों को मिला लक्ष्य

बैठक में जनपद पंचायत बरमकेला को 35 हजार, बिलाईगढ़ को 20 हजार एवं सारंगढ़ को 20 हजार, इसप्रकार कुल 75 हजार सोखता गड्डे एवं अन्य संरचनाओं का पोर्टल में एंटी करने का लक्ष्य दिया गया है। इसी तरह वन विभाग को 30 हजार, शिक्षा विभाग को 3 हजार, जिले के सभी नगरीय निकाय में कुल 10 हजार पोर्टल में एंटी करने निर्देश दिया गया।

लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर की सुरक्षा और उद्यान जीर्णोद्धार की मांग, विधायक किरण सिंह देव को सौंपा ज्ञापन

जगदलपुर/मूक पत्रिका

बिते शनिवार को महाराजा प्रवीर चंद्र शक्ति केंद्र के बूथ क्रमांक 117 के अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा की पहल पर शक्ति केंद्र के सभी बूथ अध्यक्षों और वार्डवासियों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर स्थित उद्यान के जीर्णोद्धार और मंदिर क्षेत्र को असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रखने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव को ज्ञापन सौंपा।

नगर मंत्री पश्चिम मंडल एवं महाराजा प्रवीर चंद्र शक्ति केंद्र के प्रभारी अविनाश सिंह गौतम ने बताया कि वार्डवासियों की लंबे समय से मांग थी कि लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में स्थित उद्यान का जीर्णोद्धार किया जाए और मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, ताकि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लग सके। ज्ञापन मिलने के बाद विधायक किरण सिंह देव ने



मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सिटी कोतवाली थाना प्रभारी से भी फोन पर चर्चा कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। मांगों पर त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करने पर

वार्डवासियों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। इस दौरान महाराजा प्रवीर चंद्र शक्ति केंद्र के संयोजक प्रेम सेठिया, बूथ अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, गंगोत्री चंद्रवंशी, छलेश्वर नाग, गजेन्द्र पाण्डे, बीएलए-2 पार्वती पाटनकर, सोमेश नाग और प्रफुल्ल कुमारी बघेल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

तेलंगाना में 130 माओवादियों ने किया सरेंडर, 124 हथियार और 5205 कारतूस पुलिस को सौंपे, PLGA के कई कमांडर शामिल

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार । तेलंगाना में माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। शनिवार को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) में 130 माओवादी कैडेटों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। यह आत्मसमर्पण मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में हुआ। आत्मसमर्पण करने वालों में संगठन के विभिन्न स्तरों के नेता और कैडर शामिल हैं। इनमें 3 राज्य समिति सदस्य, 10 संभागीय समिति सदस्य, 46 क्षेत्रीय समिति सदस्य और 70 पार्टी सदस्य शामिल बताए गए हैं। सभी ने मिलकर पुलिस को कुल 124 हथियार और 5205 जिंदा कारतूस सौंपे।



कई बड़े माओवादी नेता भी शामिल - आत्मसमर्पण करने वालों में संगठन के कई अहम पदों पर रहे नेता भी शामिल हैं। इनमें एंटी कालिथराम उर्फ उड्के कल्लू और कोरसा लक्खू, जो पीएलजीए बटालियन के कंपनी कमांडर रहे हैं, प्रमुख हैं। इसके अलावा चालासानी नवाथा उर्फ चंद्रा (डीके एसजेडसी सदस्य), इरपा रामू उर्फ विनोद (आरसीएम), मुचाकी उंगल उर्फ

सुधाकर और पोड्टम अरुणा उर्फ सनिकी (दोनों डीवीसीएम) सहित कई वरिष्ठ कैडेटों ने भी संगठन छोड़ दिया।

शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर हथियारों का आत्मसमर्पण माओवादी संगठन की सैन्य क्षमता को कमजोर करने वाला कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री की अपील का 2025 में मुख्यमंत्री ने माओवादी कैडेटों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की थी। सरकार को पुनर्वास नीति और इसी अपील से प्रभावित होकर कई कैडेटों ने भी शांतिपूर्ण जीवन जीने और परिवार के साथ सामान्य जीवन बिताने की इच्छा जताई है।

सहपाठीएम को 5 लाख रुपये, एसीएम या पीपीसीएम को 4 लाख रुपये और पार्टी सदस्य को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा हथियार जमा करने पर भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कुल मिलाकर 130 आत्मसमर्पित कैडेटों को लगभग 4 करोड़ 18 लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। फिलहाल सभी को 25 हजार रुपये की अंतरिम राहत प्रदान की गई है।

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने आयुष्मान कार्ड का शत- प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए



सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को दानसरा ग्राम में आयोजित सेक्टर बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। विशेष रूप से आयुष्मान कार्ड शिविर पर विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर तत्काल क्रियान्वयन के कड़े निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन लक्ष्यों की पूर्णता पर जोर देते हुए अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराना प्राथमिकता है, जिसके लिए समन्वित प्रयास आवश्यक है। इस बैठक में डिप्टी कलेक्टर सह ओआईसी (स्वास्थ्य विभाग) शिक्षा शर्मा, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर एल सिदार, जिला समन्वयक (आयुष्मान भारत) रोशन सचदेव, सेक्टर प्रभारी एवं अन्य संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

ड्रीमसिटी में नाले के किनारे बना अवैध निर्माण निगम ने किया ध्वस्त



भिलाई/मूक पत्रिका

नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ड्रीमसिटी क्षेत्र में नाले के समीप किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई निगम प्रशासन द्वारा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ड्रीमसिटी कॉलोनी उमदा, भिलाई-03 के निवासी अभिषेक मिश्रा (प्लॉट नंबर 98) ने अपने प्लॉट के सामने नाले के किनारे किए जा रहे अवैध निर्माण के संबंध में निगम प्रशासन को शिकायत दी थी। शिकायत के बाद निगम अमले द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के

दौरान पाया गया कि सरकारी भूमि पर लगभग 15 फीट गहरा तथा करीब 50 फीट चौड़ा कॉम्प्लेक्सनुमा अवैध निर्माण किया जा रहा था। निगम आयुक्त डी.एस. राजपूत के निर्देश पर राजस्व अधिकारी अरुणिमा दुबे के नेतृत्व में निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान उप अभियंता मुकेश रावे, सहायक राजस्व निरीक्षक सरोजनी यदु, दुष्प्रत चतुर्वेदी सहित निगम के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

कुपोषण पर विजय: नन्ही त्रिशूल ने दो माह में पाई नई जिंदगी, एनआरसी के प्रयासों से लौटी सामान्य श्रेणी में

बीजापुर/मूक पत्रिका

जिले में कुपोषण के खिलाफ चल रहे प्रयासों के बीच एक प्रेरक उदाहरण सामने आया है। भोपालपटनम के पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती नन्ही त्रिशूल वासम ने दो महीने के उपचार और देखभाल के बाद गंभीर कुपोषण को मात देकर सामान्य श्रेणी में वापसी कर ली है। माहिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच में त्रिशूल की स्थिति काफी चिंताजनक पाई गई थी। बच्चे का वजन और ऊंचाई मानक से काफी कम थी, जिसके कारण उसे अत्यंत गंभीर कुपोषित (ऋू) श्रेणी में रखा गया था। स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने की सलाह दी गई। शुरुआत में त्रिशूल के माता-पिता उसे एनआरसी ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। परिवार के मन में कई तरह



की आशंकाएं और झिझक थीं। ऐसे में महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई बार घर जाकर परिजनों की काउंसिलिंग की और बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। लगातार समझाव के बाद

परिवार बच्चे को भोपालपटनम के Nutrition Rehabilitation Centre में भर्ती कराने के लिए तैयार हुआ। एनआरसी में भर्ती होने के बाद त्रिशूल को विशेष पोष्टिक आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया। लगभग दो महीने तक चले उपचार और देखभाल के बाद उसके स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार होने लगा। अब त्रिशूल पूरी तरह स्वस्थ है और उसके वजन व ऊंचाई में संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गई है। चिकित्सकों के अनुसार बच्चा अब गंभीर कुपोषण की श्रेणी से बाहर आ चुका है।

कांकेर पुलिस की बड़ी कामयाबी, दुकान का शटर उखाड़ने वाले 2 शांति चोर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार

कांकेर/मूक पत्रिका

उत्तर बस्तर कांकेर की सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी सफ़लता हासिल की है। शहर के 'जय बम्बे किराना स्टोर' में चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पकड़े गए आरोपियों में एक आदतन अपराधी भी शामिल है। सुभाष वार्ड निवासी प्रार्थी नोभेप ठक्कर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 5 मार्च की रात वह अपनी दुकान ताला लगाकर घर गए थे। अगले दिन सुबह जब वह दुकान पहुंचे, तो वहां का ताला टूटा हुआ मिला। अज्ञात चोरों ने दुकान के भीतर से चिखर पैसे और खाने-पीने का सामान पार कर दिया था। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने धारा 331(4), 305(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू



की। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम ने मुखबिरो का जाल बिछाया। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर शिवा बाल्मिकी (26 वर्ष) और भरत साहू (24 वर्ष) को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल सामान और नकदी बरामद की हैकुल नकदी 1,711 रुपयेवाहन

एक मोटरसाइकिल छत 19 ब्रह्म 8188लोहे का सब्बल, पेंचकस और पेंचस। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी शिवा बाल्मिकी पहले से ही थाने का गुंडा बदमाश है और उस पर कई अन्य अपराध भी दर्ज हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। संपूर्ण कार्यवाही में पुलिस टीम निरीक्षक जितेंद्र कुमार साहू, दिनेश कुलदीप, कौशल साहू, रूद्र जुरी, रामू जुरी और अनिल मरकाम।

132 केवी सब स्टेशन की मांग तेज, कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन..

बिजली कटौती और लो वोल्टेज के विरोध में सरिया में कांग्रेस का धरना

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

सरिया क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर शनिवार 7 मार्च को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरिया ने अटल चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बिजली व्यवस्था को लेकर शासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई। धरना सुबह से शुरू होकर कई घंटों तक चलता रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरिया और आसपास के गांवों में लंबे समय से बिजली की गंभीर समस्या बनी हुई है। बार-बार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, जिससे आम जनता, किसान और छोटे व्यापारियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।



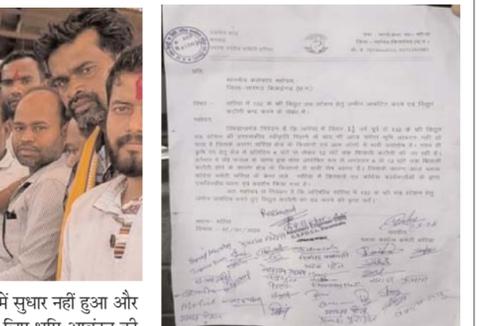
132 केवी सब स्टेशन की मांग हुई तेज- धरने के दौरान प्रमुख मांगों में सरिया क्षेत्र के लिए 132 केवी सब स्टेशन की स्थापना और उसके

बिजली विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर की समझाइश- धरना प्रदर्शन के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था से पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि क्षेत्र में 132 केवी सब स्टेशन स्थापित हो जाता है तो बिजली की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

विजली विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर की समझाइश- धरना प्रदर्शन के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था से पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि क्षेत्र में 132 केवी सब स्टेशन स्थापित हो जाता है तो बिजली की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

दिया, लेकिन चेतवनी दी कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पहले भी दिए जा चुके हैं कई ज्ञापन- ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरिया के अध्यक्ष अरसेन साहू का कहना है कि इससे पहले भी कई बार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर शासन-प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था। इसके बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि आने वाले

समय में बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और 132 केवी सब स्टेशन के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो जनता के हित में चक्का जाम जैसे बड़े आंदोलन भी किए जाएंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद- धरना प्रदर्शन में शरद यादव, अरसेन साहू, हिमांशु पाणीग्राही, अनूप पटेल, खेनराज नायक, रूप पटेल, प्रकाश पुरोहित, जयप्रकाश, हलचर राव जाधव, निखिल इनसेना, गगन साहू, संजय प्रधान, उपेंद्र पातरे, रूप इनसेना, तफसीर,



राकेश, अजय शराफ हेमराम इनसेना, सरोज, सरोज प्रधान, सरोज कर्ष, मधु साहू, गौतम, रवि सहिस, बलवी, संजय बारीक, ललित साहू, विशाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, नगर पंचायत सरिया के पार्षद और वरिष्ठ कांग्रेसजन भी बड़ी संख्या में धरने में शामिल हुए।

विश्वकप फाइनल के लिए मैच अधिकारियों का एलान

भारत-न्यूजीलैंड के बीच होगी खिताबी टक्कर

अहमदाबाद। आईसीसी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले के लिए मैच अधिकारियों की घोषणा कर दी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले के लिए मैच अधिकारियों की घोषणा कर दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह खिताबी मुकाबला रविवार यानी आठ मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

आईसीसी ने की मैच अधिकारियों की घोषणा

आईसीसी के एग्जिक्यूटिव एलीट पैनल के इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ और एलेक्स वार्फ फाइनल मुकाबले में ऑन-फील्ड अंपायर की भूमिका निभाएंगे। रिचर्ड इलिंगवर्थ लगातार दूसरी बार पुरुष टी20 विश्व कप फाइनल में अंपायरिंग करते नजर

आएंगे। इससे पहले उन्होंने 2024 टी20 विश्व कप के फाइनल में क्रिस गैफनी के साथ अंपायरिंग की थी। इलिंगवर्थ पिछले कुछ वर्षों में आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में भी अंपायरिंग कर चुके हैं। उन्होंने 2023 वनडे विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबलों में भी अंपायरिंग कर चुके हैं। उन्होंने 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप और 2023 पुरुष क्रिकेट विश्व कप में अंपायरिंग कर चुके हैं। उन्हें पिछले साल एग्जिक्यूटिव एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स में शामिल किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इलिंगवर्थ और वार्फ ने हाल ही में कोलकाता के इंडन गार्डन्स में खेले गए सेमीफाइनल में भी साथ अंपायरिंग की थी, जहां न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।



अल्लाहुद्दीन पालेकर को थर्ड

फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के अंपायर नियुक्त किया गया है। 48 वर्षीय पालेकर को मार्च 2025 में एलेक्स वार्फ के साथ आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किया गया था और उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक छह मैचों में अंपायरिंग की है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के एड्रियन होल्डस्टॉक चौथे अंपायर की भूमिका निभाएंगे, जबकि एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी की जिम्मेदारी संभालेंगे।

एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना और निकहत से रहेंगी पदकों की उम्मीद



नई दिल्ली। 28 मार्च से 11 अप्रैल तक मंगोलिया में होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और विश्व चैंपियन रही निकहत जरीन करेंगी। भारतीय मुक्केबाजी संघ ने कड़ी चयन प्रणाली के आधार पर इस चैंपियनशिप के लिए अपनी टीम का चयन किया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए चयनित किये गये संभावित खिलाड़ियों को पटियाला में चल रहे राष्ट्रीय शिविर में शामिल किया गया था। एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले मुक्केबाजों को राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में अवसर

बीफ न्यूज

आईपीएल की तैयारियों के लिए 15 मार्च को अपने घरेलू मैदान पर उतरेगी आरसीबी: प्रसाद

मुंबई। गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु (आरसीबी) आईपीएल की तैयारियों के लिए 15 मार्च को अपने घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उतरेगी। अर्धराज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) इस स्टेडियम में सभी तैयारियों को पूरा करने के इंतजाम कर रहा है। केएससीए के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद को उम्मीद है कि 15 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु (आरसीबी) टीम के एकत्रित होने से पहले एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे। आरसीबी ने इससे पहले कहा था कि वह आईपीएल 2026 के शुरुआती मैच सहित पांच लीग मैच इस स्टेडियम में खेलेगी जिसके साथ ही घरेलू मैदानों को लेकर जारी संदेश दूर हो गया था। प्रसाद ने कहा, "हां, अब भी स्टेडियम में कुछ काम बचा है और जहां तक 'हमारा सवाल है यह तय समय सीमा के अंदर पूरा हो जाएगा जो हमने महेश्वर राव की अध्यक्षता वाली (राज्य द्वारा नियुक्त) विशेषज्ञ समिति को दी है।" उन्होंने कहा, "हमने उन्हें जितना हो सका उतना सतुट कर दिया है। गौरवलेब है कि पिछले साल आरसीबी के आईपीएल खिताब जीतने के बाद हुए समारोह में हुड़दंग मचने के बाद से ही चिन्नास्वामी स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। इस कारण इसमें मैचों के आयोजन पर भी रोक लगा दी गयी थी जो अब हटा दी गयी है।

सिद्ध ने पाक क्रिकेटर आमिर पर कसा तंज, झूठी भविष्यवाणियों से कुछ नहीं होता

नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्ध ने भारतीय टीम के टी20 विश्वकप फाइनल में पहुंचने के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर पर निशाना साधते हुए उन्हें दोगी बाबा कहा है। सिद्ध ने आमिर की भविष्यवाणियों का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि भीख में सिंहासन नहीं मिलता इसके लिए मैदान में प्रदर्शन करना पड़ता है। इससे पहले आमिर ने एक टीवी शो में कहा था कि भारतीय टीम सेमीफाइनल हार जाएगी क्योंकि उसके खेल में कई जगह पर कमियां हैं पर वह गलत निकली हैं। भारतीय टीम इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल में पहुंची है। सिद्ध ने वीडियो में सिद्ध आमिर की बार-बार की गई भविष्यवाणियों की आलोचना करते हुए कहा है कि उनकी सभी बातें गलत रही हैं। आमिर ने कहा था कि भारत टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ पाएगा। साथ ही कहा कि हमारे आसपास के लोगों को झूठी भविष्यवाणी करने की बहुत आदत है। अगर सही हो जाए तो ठीक, नहीं तो उसे नजर अंदाज कर देते हैं। अगर सही हो जाए तो कहते हैं तीर चल गया, नहीं तो कहते हैं अंदाजा था और फिर अपने को ज्ञानी समझते हैं। हाथ ही कहा कि ऐसे लोग सिर्फ दोगी बाबा हैं। पहले कहा कि भारत क्वालीफाई नहीं करेगा, सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा और वेस्टइंडीज व दक्षिण अफ्रीका जीतेंगे पर दोनों ही टीमें हार गयीं। इसके बाद इंग्लैंड भी बाहर हो गयीं। उन्होंने आमिर पर तंज कसा कि खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करते हैं। यही बात है।

ईरान के फीफा विश्वकप में भाग लेने की संभावना नहीं

इराक या यूएई को मिल सकता है अवसर

लास एंजिल्स। अमेरिका और इजरायल से जारी संघर्ष को देखते ईरान का आगामी फीफा विश्व कप फुटबॉल से हटना तय है। ईरान को विश्व कप के ग्रुप जी चरण में रखा गया है और उसके तीनों ही मैच अमेरिका में होने हैं और अभी के हालातों को देखते हुए ये संभव नहीं है कि ईरान अपनी टीम भेजे। उसके मैच कैलिफोर्निया में 15 जून को न्यूजीलैंड और 21 जून को बेल्जियम के खिलाफ रखे गये हैं। इसके बाद वह 26 जून को सिएटल में मिक्स के खिलाफ पहले दौर का अपना अंतिम मुकाबला खेलना है। विश्व कप का कार्यक्रम जब बना था तब हालात अलग थे पर जिस प्रकार से अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किये हैं और जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इजरायल और खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने को निशाना



बनाया है उससे हालात काफी खराब हो गये हैं। एशियाई फुटबॉल महासंघ के उपाध्यक्ष और ईरान के शीर्ष फुटबॉल अधिकारी मेहदी ताज ने कहा, "निश्चित रूप से इस हमले के बाद हम विश्व कप में भाग लेने की उम्मीद नहीं कर सकते।" अभी यह तय नहीं है कि ईरान 11 जून से शुरू होने वाले विश्व कप के लिए अपनी टीम भेजेगा या नहीं या अमेरिका की सरकार उसकी टीम को अपने यहां आने

की अनुमति देती है या नहीं। फीफा ने अभी तक मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। ईरान ने पिछले आठ विश्व कप में से छह के लिए क्वालीफाई किया है। वह 211 टीमों की फीफा विश्व रैंकिंग में 20वें स्थान पर है। अगर ईरान विश्व कप से हट जाता है तो उसके फुटबॉल महासंघ को कम से कम 10.5 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। इसके अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि ईरान विश्व कप से हटता है तो एशिया से उसके संभावित विकल्प इराक या यूएई को शामिल कर सकता है। इराक और यूएई एशियाई क्वालीफाइंग में नौवें और दसवें स्थान पर रहे थे। इराक ने प्लेऑफ में यूएई को हरा दिया था और अब विश्व कप में जगह बनाने के लिए उसे 31 मार्च को बोलीविया या सूरीनाम के खिलाफ मैच में खेलना है। इस मैच में जीत से वह विश्व कप में खेल सकेगा।

भारत-इंग्लैंड मैच में धोनी रहे आकर्षण का केन्द्र

मुंबई। भारतीय क्रिकेट टीम ने यहां हुए दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर टी20 विश्वकप के फाइनल में पहुंच गयी है। जहां अब उसका मुकाबला रविवार को न्यूजीलैंड से होगा। भारतीय टीम का गत दिवस इंग्लैंड से हुआ सेमीफाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और इसमें भारतीय टीम 7 रनों से जीत हासिल करने में सफल रही। सेमीफाइनल मुकाबले में पूर्व भारतीय कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी स्टेडियम में उपस्थित थे और ऐसे में वह सभी के आकर्षण का केन्द्र रहे। भारतीय टीम की जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर 'थाला फॉर अ रीजन' की वायरल फ्रेज सोशल मीडिया में आने लगी।



गौरतलब है कि धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स (सोएसके) में थाला के नाम से जाना जाता है। उनकी जर्सी सात भी इसके बाद प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय रही। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर धोनी की मौजूदगी को जीत का कारण बताते हुए पोस्ट का बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने 'थाला फॉर अ रीजन' फ्रेज को बार-बार दोहराया, जो रातभर ट्रेंड करता रहा। भारतीय टीम की इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जो जीत के दौरान नंबर 7 का संयोग

सुखद रहा। भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम भी 7 विकेट पर 246 रन बनाने में सफल रही। भारतीय टीम 7 रन से जीती। इस मैच में भारतीय टीम की ओर से संजु सैमसन ने 7 छक्के लगाये। इंग्लैंड के लिए शतक लगाने वाले जैकब बेथल ने भी 7 छक्के लगाये। धोनी की जर्सी नंबर और इस फ्रेज को लेकर पिछले कुछ सालों में कई मीम्स वायरल हुए हैं, जो आम तौर पर क्रिकेट या अन्य संदर्भों में नंबर सात के दिखने पर सामने आते हैं। धोनी ने स्वयं साल 2024 में एक वीडियो में इस ट्रेंड पर बात करते हुए पाना था कि उन्हें इसके बारे में पता है, लेकिन इसकी शुरुआत का कारण पूरी तरह नहीं समझते। उन्होंने कहा 'मुझे पता है, लेकिन मुझे इसके पीछे की वजह नहीं पता।'

8 से 14 मार्च तक खेले जाएंगे एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर

हैदराबाद। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर 8 से 14 मार्च तक खेले जाएंगे। इसके लिए टीमों का भारत आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी के तहत ही सबसे पहले इटली की टीम हैदराबाद, तेलंगाना पहुंच गयी है। आठ से 14 मार्च तक होने वाले इस टूर्नामेंट में आठ देश मुकाबला करेंगे। इस टूर्नामेंट में आठ देशों शामिल रहेंगे। इसमें इटली को पूल ए में जगह मिली है। इसमें उसका सामना इंग्लैंड, कोरिया और ऑस्ट्रिया से होगा। इटली ने पहले दो बार एफआईएच हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था। उसने पहली बार 1976 में और 2018 में क्वालीफाई किया था। तब वह नौवें स्थान पर रही थी।



इस बार इटली अपना पहला मुकाबला 8 मार्च को इंग्लैंड से खेलेगी। इसके बाद 9 और 11 मार्च को ऑस्ट्रिया और कोरिया से उसके मैच हैं। इटली की महिला टीम की कप्तान, सारा पुग्लिसी ने कहा, हम अच्छी तैयारी के बाद यहां हैदराबाद पहुंचे हैं। हम एफआईएच हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई मुकाबलों की तैयारी से आये हैं।

फॉर्मूला वन ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स के कार्यक्रम में बदलाव नहीं: औल्ड

मेलबर्न। खाड़ी में जारी संघर्ष के बाद भी फॉर्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन तय समय पर ही किया जाएगा। इसकी अभ्यास रस 6 मार्च से शुरू होगी। वहीं मुख्य रस 8 मार्च को होगी। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ट्रैविस औल्ड ने कहा है कि अधिकारियों, टीम सदस्यों और ड्राइवरों पर इस संघर्ष का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसे में सत्र की इस पहली रस के कार्यक्रम में बदलाव नहीं होगा। औल्ड ने माना है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के कारण बड़े स्तर पर उड़ानों के रद्द होने से कुछ टीमों को अपनी यात्रा योजनाएं बदलनी पड़ी हैं। इसी को देखते हुए कि



फॉर्मूला वन टीम के अधिकारी इस प्रयास में लगे हैं कि ड्राइवर और टीम के लोग वैकल्पिक रास्तों से सुरक्षित रूप से मेलबर्न पहुंच सकें। औल्ड ने कहा, हर कोई रस के लिए यहां आने तैयार है, इससे प्रशंसकों को तय कार्यक्रम के

अनुसार ही रस देखने को मिलेगा जो उनके लिए भी राहत की बात है। उन्होंने कहा, कुछ ड्राइवर और कुछ टीम सदस्य पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में हैं पर ब्रिटेन और यूरोप से कई सदस्यों को आना है जिसमें रस भी शामिल हैं। ऐसे में इन्हें कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता देना होगा। मुझे भरोसा है कि वे लोग भी इस बारे में विचार कर रहे होंगे। वहीं स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो हजार एफ वन कर्मचारियों को पश्चिम एशिया में फंसने से बचने के लिए यूरोप से मेलबर्न के लिए अपनी उड़ानों को फिर से पुनर्बिधित करना होगा। फार्मुला वन करीब 500 स्टाफर्स को तीन विशेष उड़ानों से लाने का प्रयास कर रहा है।



लंदन में प्रीमियर लीग फुटबॉल में खेलती हुई टोटेनहम और क्रिस्टल की टीमें।

कुछ दिन अकेले रहना चाहता था, ऑटोग्राफ न देने पर फैंस से माफी मांगी खराब चेस फॉर्म पर बोले डी गुकेश

मुंबई। प्राग इंटरनेशनल चैस फेस्टिवल 2026 के सातवें राउंड में भारत के वर्ल्ड चैंपियन डी. गुकेश ने ईरान के परहम मगसूदलू के खिलाफ ड्रॉ खेला। गुकेश प्राग में अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए हैं। उन्होंने तीन मैच हारे और चार ड्रॉ खेले हैं। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन के लिए यह टूर्नामेंट काफी कठिन रहा है। गुकेश ने फैंस से माफी मांगी सातवें राउंड के बाद गुकेश ने फैंस से माफी मांगी और खराब प्रदर्शन को इसकी वजह बताया। मैच के बाद ग्रैंडमास्टर कर्टी त्सात्सालाशविली से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे रोज आने वाले फैंस की सराहना करते हैं, लेकिन कुछ दिनों वे



अकेले रहना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आमतौर पर वे मैच के बाद ऑटोग्राफ और फोटो देते हैं, लेकिन यहां उनका मूड ठीक नहीं रहा, इसके लिए वे माफी चाहते हैं। हालांकि फैंस का समर्थन उनके लिए बहुत मायने रखता है। माता-पिता बड़ा सहारा हैं अपने फॉर्म पर गुकेश ने माना कि वे अच्छा नहीं खेल



पाए और मिले मौकों का फायदा नहीं उठा सके। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए खराब टूर्नामेंट रहा। गुकेश ने बताया कि वे कोच ग्रजेगोरज गाजेव्स्की के साथ प्राग आए हैं और मेटल कंडीशनिंग कोच पैडी अष्टन के साथ काम जारी है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम और खासकर माता-पिता उनका बड़ा सहारा हैं।

मुश्किल स्थिति में टिके रहना उनकी ताकत रही

त्सात्सालाशविली ने कहा कि साथी कमेंटरेटर और क्रोएशियाई खिलाड़ी अलोयिजे जानकोविच अक्सर गुकेश को बेहतर तरीके से खिलवाड़ियों में गिनाते हैं। इस पर गुकेश ने कहा कि मुश्किल स्थिति में टिके रहना उनकी ताकत रही है, लेकिन इस टूर्नामेंट में कुछ भी उनके पक्ष में काम नहीं आया।

लाइव चेस रैंकिंग में गुकेश 20वें स्थान पर पहुंच गए

वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को प्राग इंटरनेशनल चैस फेस्टिवल 2026 में भारतीय ग्रैंडमास्टर अरविंद चिंदबरम से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद लाइव चेस रैंकिंग में गुकेश 20वें स्थान पर पहुंच गए। वे टूर्नामेंट में आखिरी नंबर पर चल रहे हैं।

